राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 282 | रायपुर | शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

Ro-45521/70

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम से की खालिस्तानियों पर एक्शन की अपील

लोकतंत्र में कट्टरपंथ की जगह नहीं

एजेंसी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच खालिस्तानी कट्टरपंथ पर भी चर्चा हुई. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की मीटिंग के दौरान खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई. मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कट्टरवाद और हिंसक चरमपंथ की कोई जगह नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद का लोकतांत्रिक समाजों में कोई स्थान नहीं है।

यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ़लंकेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ़सरे भारत में खोलेंगी कैंपस

नई दिल्ली, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि यूनिवर्सिटी ऑफ़लंकेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ़सरे को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है. यह घोषणा प्रधानमंत्री स्टारमर के भारत के पहले दौरे के दौरान की गई. इन दोनों विश्वविद्यालयों के अनुमोदन के साथ ही भारत में यूके की शैक्षणिक संस्थानों की संख्या नौ हो गई है जो ऑफ़शोर कैंपस स्थापित कर रहे हैं. इससे पहले इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथैम्पटन ने दिल्ली में अपना कैंपस खोला था, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ़ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफ़ास्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कॉवेंट्री अगले साल से अपने कैंपस शुरू करने वाले हैं.

बिहार में पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने लगभग 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की

एजेंसी।

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। बिहार में विभिन्न चरणों के चुनाव सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए लगभग 8.5 लाख चुनाव निर्वाचन अधिकारियों को तैनात किया गया है। तैनात किए जाने वाले कर्मियों में लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएँ भी शामिल हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है

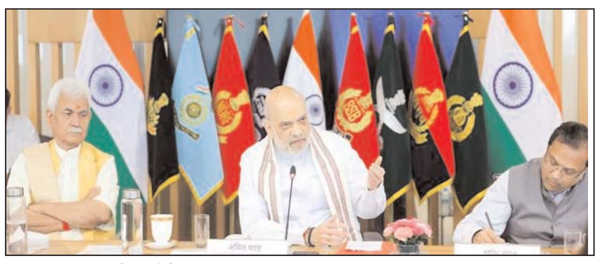

पीआईबी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, थल सेनाध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदेशक तथा भारत सरकार, सेना और जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

कोल्ड्रिफ के बाद दो और कफ सिरप में मिला 'जानलेवा केमिकल', सरकार ने लगाया बैन

गांधीनगर संवाददाता।

मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 20 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब गुजरात में भी दो अन्य कफ सिरप में जानलेवा केमिकल पाए जाने से हड़कंप मच गया है। जांच में इन सिरप के सैंपल में भी वही जहरीला रसायन, डायएथिलीन ग्लाइकॉल खतरनाक स्तर पर पाया गया है जो मध्य प्रदेश के बच्चों की मौत का कारण बना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तत्काल दोनों कंपनियों के विशिष्ट बैचों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 7 अक्टूबर को जारी की गई सूचना के अनुसार, 'रेस्पिफ्रेश टीआर' और 'रिलीफ' नामक कफ सिरप के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। 'रेस्पिफ्रेश टीआर' का निर्माण अहमदाबाद की रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स और 'रिलीफ' का निर्माण शेखपुर की शेप फार्मा करती है। मध्य प्रदेश FDCA ने भी आधिकारिक तौर पर इन सिरप में DEG की अत्यधिक मात्रा की पुष्टि की है। जिन बैचों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें रेस्पिफ्रेश टीआर का बैच नंबर R01GL2523 और रिलीफ कफ सिरप का बैच नंबर LSL25160 शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की

आतंक और वार्ता साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते तथा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते : रक्षा मंत्री

पीआईबी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर, 2025 को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मार्लेस के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय बैठक की। ये बैठक भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पाँच वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दौहराया।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को रेखांकित करने वाले गहरे सांस्कृतिक संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज़ोर दिया और कहा कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा के अनुरूप रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय विस्तार देखा है। यह बातचीत तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुईः सूचना साझाकरण पर एक समझौता, पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और संयुक्त स्टाफवार्ता की स्थापना पर संदर्भ की शर्तें। बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खतरे के संबंध में भारत के रुख को दोहराया कि ''आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते तथा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते''। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट होने का भी आग्रह किया।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 680 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए

पीआईबी - भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफ सी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंबद्ध (मूलभूत) अनुदान की पहली किस्त के रूप में 680.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि राज्य भर की पात्र 3,224 ग्राम पंचायतों, 335 ब्लॉक पंचायतों और 21 जिला परिषदों के लिए 6 अक्टूबर 2025 को जारी की गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पश्चिम बंगाल को कुल 4,181.23 करोड़ रुपए ।

चुनाव आयोग ने चेताया, प्रचार में एआई आधारित भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल

नई दिल्ली एजेंसी

बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर से चुनावी प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चेताया है कि वे प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित गलत और भ्रामक वीडियो का इस्तेमाल न करें। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ जमीनी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।

आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकॉर्ड और कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए। निजी जीवन पर टिप्पणी करना पूरी तरह निषिद्ध है। इसके अलावा, किसी भी राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना पुष्टि के आरोप या जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश करना गलत है और इसे सख्ती से रोका जाएगा। चुनाव आयोग ने गहरी चिंता जताई है कि कुछ लोग एआई टूल्स की मदद से 'डीप फेक' वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल को दूषित किया जा सकता है।

विश्व | भारत-ब्रिटेन संबंधों में आ गई नई ऊर्जा

प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बात

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस बैठक में व्यापार, संस्कृति और खेल जगत में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की आपसी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफ्टीए) देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले ही हासिल कर लेने का भरोसा जताया। मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के

साथ कंपनियों के सीईओ के एक मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) ऐसे समय में स्थिरता प्रदान करेगा जब दुनिया अस्थिरता का सामना कर रही है। मोदी ने कहा कि आज भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर है। मुझे विश्वास है कि इसे दोगुना करने का लक्ष्य 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालयों के परिसर (कैंपस) भारत में खुलने जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध ऐसे समय में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जब विश्व अनिश्चितता के दौर से जूझ रहा है। मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत के बाद ये टिप्पणी की। मोदी ने कहा कि जुलाई में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं कारोबार समझौते से दोनों देशों के बीच आयात लागत कम होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के उद्योगों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

बंधकों को रिहा करेगा हमास, इजरायली सेना की होगी वापसी

गाजा शांति प्रस्ताव के पहले फेज का ट्रंप ने किया ऐलान

न्यूयॉर्क एजेंसी

इजरायल और हमास शांति समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर इजरायल और हमास ने सहमति जताई है। इस चरण की शुरुआत हमास की ओर से बंधकों की रिहाई और इजरायली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी से होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक पोस्ट में लिखा, योजना के पहले चरण की स्वीकृति के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजरायल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय व नैतिक विजय है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई और हमारे महान मित्र व सहयोगी राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों से, हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट में लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इजरायल की सुरक्षा व हमारे बंधकों की आजादी के प्रति अटूट समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं।

वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा, सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। यह अरब और मुस्लिम देश, इजरायल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है। हम कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया। दो साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर बर्बर हमला किया था, जिससे यह संघर्ष शुरू हुआ था। हमास ने उस हमले में लगभग 1,250 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास संगठन को गाजा से लगभग खत्म कर दिया है। हमास से सभी टॉप लीडर्स को इजरायल ने मार गिराया। हालांकि, हमास के आतंकियों पर इजरायल की कार्रवाई से गाजा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया।

इन दवाओं पर लगे टैरिफ में यूएस कर सकता है बदलाव, ट्रंप आने वाले दिनों में कर सकते हैं घोषणा

एजेंसी

वाशिंगटन ,अमेरिका से एक राहतभरी खबर सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपने फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले 100 प्रतिशत टैरिफ के दायरे से जेनेरिक दवाओं को बाहर रख सकता है। लंबे समय से इस मुद्दे पर चल रही बहस के बाद, प्रशासन ने संकेत दिया है कि विदेशी देशों से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर शुल्क लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह फैसला भारत के लिए खास तौर पर सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक है। इस खबर का असर बाजार में भी दिखा और फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन आने वाले हफ्तों में फार्मा टैरिफ नीति में बदलाव की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार संभवतः जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से अलग रखेगी। बता दें कि ब्रांडेड और पेटेंटेड विदेशी फार्मा उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के बाद से ही जेनेरिक दवाओं के भविष्य को लेकर उद्योग जगत में अनिश्चितता बनी हुई थी।

अब इन संकेतों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत समेत अन्य देशों के फार्मा निर्यातकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं, शेयर बाजार में इस खबर के बाद निवेशकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है और फार्मा सेक्टर में तेजी का रुझान जारी है।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल में भोजन का ठेका लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये

0 जिला अस्पताल का मामला

0 कलेक्टर ने कहा भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा

0 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ हितग्राहियों को देने के निर्देश

0 पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं

जशपुर, । कलेक्टर रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन , मुख्यमंत्री की घोषणा और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा के तहत स्वीकृति कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें इसके साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जिला अस्पताल में मरीजों को दी जा रही भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में जिस अधि स्व सहायता समूह द्वारा भोजन का ठेका दिया गया है। उसकी शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत में समूह द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर ठेका प्राप्त किया गया है। जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधि श्री स्व सहायता समूह पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके विभागीय जांच के माध्यम से शासकीय सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ हितग्राहियों को देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के बोझ से मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठाएं योजना के तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा एक किलोवाट सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपए और दो किलोवाट पर 60 हजार की सब्सिडी इसी प्रकार तीन किलोवाट से दस किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 30 हजार रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर ने धरती आबा योजनान्तर्गत चलाये जा रहे आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत संचालित विशेष कार्यक्रम के तहत विज़न 2030 के अंतर्गत ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने एवं सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजनांतर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा।

धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन अनिवार्य : किसान 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन

एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क

रायपुर, संवाददाता।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या

रिसाली निगम का वार्ड 13 बना 'ओपन खटाल', जनता बेहाल - निगम चुप, सड़कों की मालिक मवेशियो

'लोकशक्ति

भिलाई/रिसाली, । रिसाली नगर निगम के वार्ड 13 मरोदा टैंक क्षेत्र में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा इलाका एक खुले खटाल जैसा नजर आने लगा है। रहवासी क्षेत्र में खुलेआम खटालों का संचालन हो रहा है, और दूध निकालने के बाद मवेशियों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। दिनभर यह जानवर पूरे वार्ड में घूमते रहते हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि इन सबके बावजूद नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मौन और निष्क्रिय बना हुआ है।

इलाके के रहवासी लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि खटाल संचालक जानबूझकर मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि निगम कोई कार्यवाही नहीं करेगा। इसी का नतीजा है कि आज पूरे वार्ड 13 और आसपास के वार्ड 12 में सड़कों से लेकर गलियों तक, मवेशियों का कब्जा हो चुका है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए तो यह रास्ते जानलेवा बनते जा रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निगम की यह चुप्पी एक तरह से लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध की श्रेणी में आती है। जब देश के कई हिस्सों में आवारा पशुओं के कारण जानलेवा दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तब रिसाली निगम द्वारा इस समस्या की अनदेखी बेहद चौंकाने वाली है। आम जनता सवाल कर रही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है?

मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि हाईकोर्ट तक इस विषय पर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवारा पशुओं को सार्वजनिक सड़कों से हटाया जाए, क्योंकि यह आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसके बावजूद रिसाली नगर निगम का यह ढुलमुल रवैया बताता है कि या तो जिम्मेदार अफ़सरों को स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है, या वे जानबूझकर इस पर आंख मूंदे हुए हैं।

सेक्टर-1 में भिखारी के वेश में घुसे चोरों का गिरोह, घर से लैपटॉप चोरी सीसीटीवी में महिला और बच्चा भी नजर आए

भिलाई, । शहर के सेक्टर-1 में रविवार सुबह एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच टी. वी. नागेश्वर राव के घर में एक भिखारी के वेश में आए व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसपैठ की और लैपटॉप चोरी कर फरार हो गया। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अकेला नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ एक महिला और एक बच्चा भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह साफहै कि यह कोई अकेले का काम नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह की करतूत है जो परिवार सहित चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। टी. वी. नागेश्वर राव ने बताया कि सुबह के समय घर के सभी सदस्य अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। उनका बेटा, जो रात में लैपटॉप पर काम कर रहा था, सुबह उसे वहीं छोड़कर बाहर चला गया था। उसी समय यह गिरोह, भिखारी के वेश में, घर के बाहर आवाजें लगाता रहा। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मौका देखकर यह लोग सीधे घर के अंदर घुस गए और तलाशी शुरू कर दी। गिरोह ने पूरे घर में इधर-उधर तलाशी ली और कीमती सामान की तलाश के बाद *लैपटॉप चोरी कर फरार हो गया*। घर के सदस्यों को इस चोरी का पता तब चला जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। राव ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं हुआ है *आसपास के इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं*, जिससे लगता है कि यह एक लगातार सक्रिय गिरोह है जो भोले-भाले लोगों को निशाना बना रहा है।

नगर पंचायत पुसौर में हुआ 15 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

धमतरी, । फिट इंडिया मूवमेंट को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से आज से सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। धमतरी जिले के चारों विकासखंडों रावां (धमतरी), पचपेड़ी (कुरूद), कुकरेल (नगरी) एवं भेंड्री (मगरलोड) में ग्रामीण स्तर पर आयोजित इस खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्रामीण दर्शकों ने भी पारंपरिक खेलों को पुनः जीवंत होते देख अपने बचपन को याद किया और सांसद महासमुंद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी के इस प्रयास की सराहना की।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महापौर श्री रामू रोहरा, श्रीमती ज्योति साहू (अध्यक्ष, नगर पंचायत आमदी), श्री विनय जैन, श्री अमन राव, श्रीमती गीतेश्वरी साहू (अध्यक्ष, जनपद पंचायत कुरूद) एवं श्री सतीश जैन (उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत कुरूद) की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिले के सभी चार विकासखंडों में एक साथ हुए इस शुभारंभ से ग्रामीण खेल संस्कृति में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी एवं सांसद कांकेर श्री भोजराज नाग के मार्गदर्शन में आयोजित इस खेल महोत्सव की थीम ÷फिट युवा फॉर विकसित भारत रखी गई है। प्रतियोगिताओं में युवाओं को 14 से 19 वर्ष एवं 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बांटकर व्यक्तिगत एवं दलगत खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 100 मीटर, 400 मीटर, गेड़ी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गिल्ली डंडा जैसे व्यक्तिगत खेलों के साथ खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और रस्साकसी जैसे दलगत खेल शामिल हैं। आने वाले दिनों में क्रमशः 9, 11, 14 एवं 17 अक्टूबर को जिले के विभिन्न संकुलों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं के पश्चात विधानसभा स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संकुलों के चयनित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। विकासखंड स्तर पर संयोजक के रूप में निर्मला सिन्हा (रावां), सुरेश निषाद (पचपेड़ी), वेदराम साहू (भेंड्री, मगरलोड) एवं धनेश सोरी (कुकरेल) की भूमिका उल्लेखनीय रही। इसके साथ ही जिले के व्यायाम शिक्षकों ने निर्णायक के रूप में प्रतियोगिताओं को निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

स्वर्णकार समाज का भव्य आयोजन सम्पन्न

हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई महाराज अजमेर अजमीढ़ देव जी की जयंती

0 समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वक्ताओं ने लिया संगठन और प्रगति का संकल्प

मनेन्द्रगढ़, संवाददाता

केंद्रीय समिति स्वजातीय स्वर्णकार समाज छत्तीसगढ़ और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान भवन मनेन्द्रगढ़ में समाज के आराध्य देव, संस्थापक श्री श्री 1008 महाराज अजमीढ़ देव जी की जयंती का भव्य आयोजन अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों और समाज के वरिष्ठजनों द्वारा महाराज अजमीढ़ देव जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। इसके बाद समाज के जनप्रतिनिधियों ने आरती कर समाज के उत्थान एवं एकता की मंगलकामना की।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम

जयंती समारोह में बच्चों के बीच रंगोली, पेंटिंग और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोटे-छोटे बच्चों ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैली में शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। रंगोली प्रतियोगिता में समाज की परंपराओं और एकता के चित्र उकेरे गए वहीं नृत्य प्रतियोगिता में देशभक्ति और सांस्कृतिक धुनों पर तालियाँ गूंज उठीं।

कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।

वक्ताओं ने समाजिक एकता पर दिया बल इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने समाज की एकता और संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पूर्व विधायक सुनील सराफ ने कहा कि अजमीढ़ देव जी ने हमें संगठन, परिश्रम और सेवा का जो संदेश दिया है, उसे अपनाकर ही समाज नई ऊँचाइयाँ छू सकता है। इसी प्रकार राजेश सोनी, विपिन प्रसाद सराफ विष्णु सराफ रविन्द्र सोनी, मनोज कुमार सोनी एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि स्वर्णकार समाज हमेशा से देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रहा है और आज युवा पीढ़ी में जागृति देखकर गर्व होता है।

बड़ी संख्या में समाजजन रहे उपस्थित

कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुनील सराफ राजेश सोनी, विपिन प्रसाद सराफ छैदिलाल सराफ विष्णु सराफ मनोज कुमार सोनी, दीपक सोनी, हरीश प्रसाद सोनी, संजीव चैतन्य सोनी, नरेश सोनी, बिहारी लाल सराफ बदरुद्दीन सोनी, विकास सोनी (निक्की), कृष्णा सोनी, श्रीमती राजकुमारी सोनी, जयकुमार सोनी, विशेष सोनी, अमिता सोनी, रविंद्र सोनी, श्रीमती ज्योति सोनी, आकाश सोनी, पिंकी सोनी, श्रीमती वंदना सोनी सहित केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समिति के पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं एवं बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

सांसद खेल महोत्सव से ग्रामीण अंचल में बढ़ी खेल भावना –फिट इंडिया मूवमेंट को मिला नया आयाम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मनेंद्रगढ़ में भव्य पथ संचलन— स्वयं सेवकों ने दिया राष्ट्र समर्पण का संदेश

मनेंद्रगढ़, संवाददाता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मनेंद्रगढ़ द्वारा संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नगर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मंदिर से हुआ। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन, एकता और राष्ट्रनिष्ठा का परिचय देते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से संचलन करते हुए श्री राम मंदिर मैदान पहुँचे।

मार्ग में नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय श्रीराम के उद्घोष से नगर का वातावरण देशभक्ति से गुंजायमान रहा।

मुख्य अतिथि एस. के. शर्मा (पूर्व प्राचार्य, मनेंद्रगढ़) ने कहा संघ व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। एक स्वयंसेवक जब अपने जीवन में सेवा, अनुशासन और संगठन के भाव को धारण करता है, तब समाज में सशक्त परिवर्तन स्वतः होता है। आने वाला शताब्दी काल राष्ट्र के उत्थान और विश्व में भारत के नेतृत्व का काल होगा।

विभाग प्रमुख (धर्मजागरण) दीपक राम ने अपने उद्बोधन में कहा – भारत की पहचान उसके धर्म, संस्कृति और संस्कारों से है। धर्मजागरण का अर्थ है – प्रत्येक व्यक्ति में निहित कर्तव्य भावना को जागृत करना। यदि हम अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे, तो कोई भी शक्ति हमें विभाजित नहीं कर सकती।

प्रांत परियोजना प्रमुख (ग्राम जागरण प्रकल्प) शंकरदयाल साव, कोरबा ने कहा कि गांव भारत की आत्मा हैं। ग्राम जागरण के माध्यम से संघ यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर, संगठित और संस्कारित बने। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का जो मार्ग संघ ने दिखाया है, वही भारत को विश्वगुरु बनाने का पथ है।

कार्यक्रम में नीरज अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद केसरी, रामचरित द्विवेदी, राहुल सिंह,धर्मेंद्र पटवा,आकाश दुआ, आशीष मजूमदार, विवेक अग्रवाल, ज्ञानेश केशरवानी,अनिल मित्तल समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, गणवेशधारी विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक और नगरवासी उपस्थित रहे।

कलेक्टर कांफ्रेंस 12 को मुख्यमंत्री साय जिलों की योजनाओं का लेंगे फीडबैक गिरदावरी स्वास्थ्य-शिक्षा पर होगी बात, जीएडी ने जारी किया एजेंड़ा

संवाददाता

कलेक्टर कांफ्रेंस के लिए विभिन्न विभागों के 18 विषयों को लेकर एजेंडा जारी कर दिया है। सभी संभागायुक्तों एवं कलेक्टर्स को जीएडी से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि 12 अक्टूबर को कलेक्टर कांफ्रेंस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे। विभागों वार जिन एजेंड़े पर प्रस्तुतीकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जाएगा। जिला कलेक्टरों को धान खरीदी और मक्का खरीदी की तैयारी के संबंध में विशेष ध्यान रखा गया है।

कांफ्रेंस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण एजेंडें में समर्थन मूल्य पर धान व मक्का की खरीदी की तैयारी को शामिल किया गया है। खाद्य विभाग इस संबंध में प्रस्तुतीकरण देगा। इसमें कृषक पंजीयन, गिरदावरी का सत्यापन, खरीदी केन्द्रों की तैयारी, खरीदी केन्द्र प्रभारी की तैनाती, बारदानों की व्यवस्था, बिचौलियों व राज्य के बाहर से आने वाले धान की रोकथाम और वर्ष 2024-25 के धान का उठाव पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की स्थिति पर कृषि विभाग जानकारी प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा पर ऊर्जा विभाग प्रस्तुती करण देगा।

स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों पर जिलों की स्थिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी विषय, आरोग्य मंदिर के संचालन की स्थिति एनसीडी स्क्रीनिंग व उपचार, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति, सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति, टीबी, मलेरिया तथा डेंगू की रोकथाम की व्यवस्था, मितानिन दवा पेटी हेतु औषधियों की व्यवस्था, पीएमएभीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण देगा।

कुपोषण में कमी लाने हेतु रणनीति पर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रस्तुतीकरएा देगा। साथ ही सक्षम आंगनबाडी, सुपोषण चौपाल, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती, पोषण एप का उपयोग, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना जैसे विषयों पर जिले से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

शिक्षा और आदिम जाति की योजनाओं पर चर्चा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार कार्यक्रमों पर शिक्षा विभाग जानकारी देगा। एनईपी का प्रभावी क्रियान्वयन, 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण, शिक्षकों की उपस्थिति, पीएम पोषण, सरस्वती सायकल वितरण, पीएम श्री योजना, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन, छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण, एकलव्य विद्यालयों की स्थापना व संचालन,

आवास योजना के लक्ष्य की समीक्षा

मिशन अमृत 2.0 का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन विभाग इस संबंध में जानकारी देगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग स्किलिंग तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

रोज़गार मेलों का आयोजन के संबंध में विभाग जानकारी देगा।

ई-सेवाओं की स्थिति पर चर्चा

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति, ई-सेवाएं एवं लोक सेवा गारंटी सामान्य प्रशासन विभाग व सूचना प्राद्यौगिकी विभाग, मोबाईल टावर्स की स्थिति इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, शासकीय खरीदी में पारदर्शिता वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, हितग्राही मूलक योजनाओं में ई-केवायसी एवं डीबीटी द्वारा भुगतान, पूँजीगत व्यय सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाना, शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जैसे विषयों पर जिला कलेक्टर्स से बात की जाएगी।

कराटे जैसी विधा युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मरक्षा की भावना को मजबूत करती हैं : रंजना साहू

0 धमतरी में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का हुआ भव्य समापन, मुख्य अतिथि रहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू, 364 खिलाड़ियों ने लिया भाग, विजयी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित धमतरी और रायपुर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

धमतरी,(आरएनएस)। अम्बेडकर वार्ड स्थित इंडोर हॉल में आयोजित 7वीं राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का समापन समारोह भव्यता एवं उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कराटे चैंपियनशिप में 09 वर्ष से लेकर 60 प्लस वर्ष के महिला एवं पुरुष कुल 364 खिलाड़ियों ने अपने खेल का हुनर दिखाएं जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी जिला सहित रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा सहित अन्य जिलों से प्रतिभागियों ने पूरी उत्साह से भाग लिए, कराटे प्रतियोगिता में धमतरी और रायपुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा।अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शशि पवार ने की। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कविन्द्र जैन, रोहितास मिश्रा, श्री दिलीप पटेल, गायत्री सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन की सफलता का श्रेय श्री अशोक सिन्हा एवं उनकी समर्पित टीम को दिया गया, जिन्हें सभी अतिथियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से केवल शरीर ही नहीं, मन और चरित्र का भी विकास होता है। कराटे जैसी विधा युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मरक्षा की भावना को मजबूत करती है। मैं आयोजन समिति को बधाई देती हूं जिन्होंने इतने भव्य स्तर पर इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। विजयी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आप राज्य और देश का नाम रोशन करें, यही मेरी कामना है।

छत्तीसगढ़ की प्रतिभा भी चमकेगी अंतरिक्ष में

प्रोजेक्ट अंतरिक्ष' : विद्यार्थियों को इसरो वैज्ञानिकों से मिली प्रेरणा*

इसरो SAC अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉ एन.एम. देसाई ने किया विद्यार्थियों से संवाद, कहा प्रोजेक्ट अंतरिक्ष सराहनीय कार्य, इससे प्रदेश के बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बढ़ेगी रुचि*

लोकशक्ति

रायपुर, विद्यार्थियों में अथाह अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाने, जानकारी प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, प्रेक्षागृह में 'प्रोजेक्ट अंतरिक्ष' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन रायपुर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तथा आईडीवायएम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (अहमदाबाद) के डायरेक्टर डॉ. एन. एम. देसाई, ग्रुप डायरेक्टर डॉ. डी. के. पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दीपक सिंह तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सम्मिलित हुए। डायरेक्टर डॉ. देसाई ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के साथ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों का अवलोकन किया एवं उनकी सराहना की। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि एक ही मंच पर जहाँ देश के प्रख्यात वैज्ञानिक उपस्थित थे, वहीं देश के वीर जवान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉ. देसाई ने कारगिल युद्ध एवं 1971 के युद्ध के वीर सपूत ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. प्रणव कुमार लहरी तथा कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री शमशेर सिंह कक्कड़ का सम्मान कर देश के प्रति उनके योगदान को नमन किया। अपने संबोधन में डॉ. देसाई ने इसरो की स्थापना से लेकर आज तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उसके योगदान की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया, मंगलयान-2 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिस रूप में हमने इस परियोजना की परिकल्पना की है, उसी दिशा में इसे आकार दिया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 2028 से 2030 के बीच पूरी होगी। मंगलयान-2 को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना है। चंद्रमा की तुलना में मंगल पर उतरना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि वहाँ पतला वायुमंडल मौजूद है। हम पैराशूट और मोटराइज्ड वाहनों की सहायता से इसे सुरक्षित रूप से उतारेंगे। मंगलयान को पृथ्वी से मंगल तक पहुँचने में लगभग 10 महीने का समय लगेगा तथा इसका संपूर्ण नियंत्रण पृथ्वी से ही किया जाएगा। भारत उन चुनिंदा 2–3 देशों में शामिल होगा, जिन्होंने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की होगी।

उन्होंने आगे कहा, अमेरिकी, रूसी और चीनी अंतरिक्ष एजेंसियाँ इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, किंतु भारत अब यूरोपीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के समकक्ष पहुँच चुका है। हमारा लक्ष्य विश्व की नंबर वन स्पेस एजेंसी बनना है, जिसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। भारत आत्मनिर्भर अंतरिक्ष उद्योग की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे यदि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखेंगे, तो प्रदेश भी शासन एवं विकास के क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रयोग से उल्लेखनीय प्रगति कर सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा संचालित *प्रोजेक्ट अंतरिक्ष* कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्पेस सेंटर एवं अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे विज्ञान एवं गणित के प्रति उनकी रुचि और उत्सुकता में वृद्धि होगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रेक्षागृह में उपस्थित स्कूली एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्दे के पीछे कार्य करने वाले कर्मयोद्धा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई, छत्तीसगढ़ की माटी के वीर सपूत ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. प्रणब कुमार लहरी तथा कर्नल (सेवानिवृत्त) शमशेर सिंह कक्कड़ विशेष रूप से उपस्थित हैं। मैं इसरो परिवार एवं प्रशासन की ओर से आप दोनों छत्तीसगढ़ के गौरव पुत्रों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ।

डॉ. सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इसरो से जुड़ें और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना योगदान दें। आने वाले समय में जब कोई नया प्रक्षेपण (लॉन्च) हो, तो हम गर्व से कह सकें कि उसे लीड करने वाला वैज्ञानिक हमारे छत्तीसगढ़ का है। उन्होंने बताया कि इसरो की टीम ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को सैद्धांतिक सहमति दी है कि भविष्य में साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं फिजिक्स के इच्छुक विद्यार्थियों को इसरो के अहमदाबाद केंद्र में इंटर्नशिप हेतु भेजा जाएगा। इसके लिए शासन एवं प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन आईएएस एवं जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन तथा डीईओ श्री हिमांशु भारती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार घोषित करे धान खरीदी 1 नवंबर से तथा 3286 रू. के भाव से होगी : दीपक बैज

जल जीवन मिशन में कार्य पूर्णता में रायपुर दूसरे स्थान पर

o जिले के 247 गांवों में योजना पूर्ण, पंचायतें कर रहीं जल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन-संधारण

o मिशन के तहत जिले में प्रस्तावित 393 पानी टंकियों में से 377 का निर्माण पूर्ण, 16 प्रगतिरत

o नल जल योजनाओं के 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण, मार्च-2026 तक 126 और गांवों के काम होंगे पूरा

रायपुर, लोकशक्ति।

हर घर नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में कार्य पूर्णता के मामले में रायपुर जिला धमतरी के बाद राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहां 95 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। रायपुर जिले में मिशन के अंतर्गत शामिल 477 गांवों में से 247 में काम पूर्ण कर जल आपूर्ति प्रारंभ की जा चुकी है। इन गांवों में नल जल योजनाओं को संचालन और संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। अब वहां ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का संचालन व संधारण कर रही हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, रायपुर के कार्यपालन अभियंता श्री अनिल कुमार बच्चन ने बताया कि मार्च-2026 तक रायपुर जिले के 126 और गांवों में सभी कार्यों को पूर्ण कर हर घर नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में रायपुर जिले के सभी 477 गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कुल 393 पानी टंकिया बनाई जाएंगी जिनमें से 377 का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा शेष 16 पानी टंकियां निर्माणाधीन हैं। श्री बच्चन ने बताया कि रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाएं बनाने तथा स्वीकृति का कार्य वर्ष 2020-21 में प्रारंभ हुआ था। अलग-अलग चरणों में अलग-अलग गांवों के लिए योजना बनाकर इसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि सभी गांवों में कार्यों के निविदाएं ऑनलाइन आंमत्रित की गई हैं तथा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्यादेश जारी किए गए हैं।

140 साल पुरानी कांग्रेस संगठन सृजन के लिए विवश हो, यह वैचारिक कंगाली व दयनीय दशा की बड़ी मिसाल : भाजपा

प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा : कांग्रेस नेता एक परिवार के चरण छूने में खप गए, खप रहे हैं; लेकिन कार्यकर्ताओं के मन को कभी छू नहीं पाए

0 एक परिवार के आंगन में सत्ता-सिंहासन को कैद करके रख देने की अलोकतांत्रिक और परिवारवादी मानसिकता ने कांग्रेस को दयनीय हालत में पहुँचा दिया

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 140 साल पुरानी हो चली कांग्रेस को अब फिर संगठन सृजन के लिए विवश होना पड़ रहा है, एक राजनीतिक दल के लिए वैचारिक कंगाली और दयनीय दशा की इससे बड़ी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। श्री ठाकुर ने कहा कि एक परिवार के आंगन में सत्ता-सिंहासन को कैद करके रख देने की नितांत अलोकतांत्रिक और परिवारवादी मानसिकता ने कांग्रेस को आज इस हालत में पहुँचा दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं से भरोसा उठ चुका है, शायद इसी कारण से यहाँ जिला अध्यक्ष बनाने के लिए फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और इस काम के लिए ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। यहाँ के नेताओं की आपसी सिर-फुटव्वल के कारण कांग्रेस कई धड़ों में बँटी हुई साफ नजर आ रही है और अब कांग्रेस हाईकमान को जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तक के काम में सीधी दखल देनी पड़ रही है। कांग्रेस का गुटीय घमासान अब कांग्रेस में राजनीतिक आपदा का रूप ले चुका है। कांग्रेस हाईकमान को कभी भी आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है, शायद इसीलिए बैज को फ्री हैंड नहीं दिया गया और दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता एक परिवार के चरण छूने में खप गए, खप रहे हैं; लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के मन को कभी छू नहीं पाए। यह स्थिति छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में है और इसीलिए पिछले 2014 से कांग्रेस धीरे-धीरे देश के कुछ राज्यों तक ही सिमटकर रह गई है। इससे कार्यकर्ताओं में भारी हताशा और निराशा है और अब वे कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं।

प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत जिले के आंगनबाड़ी एवं शासकीय स्कूलों में बच्चों की हुई निःशुल्क हृदय जांच

रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना ÷प्रोजेक्ट धड़कन÷ के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज आंगनबाड़ी क्रमांक 1, 2 ,3 सिवनी, आरंग में 98 बच्चों की जांच की गई। जिसमें 49 छात्र एवं 49 छात्राएं शामिल रही। जिसमें कोई भी बच्चा सस्पेक्टेड नहीं मिला। शिविर के दौरान बच्चों की जांच तेज धड़कन, वजन न बढ़ना, शरीर में नीलापन, बार-बार सर्दी-खांसी, सांस लेने में तकलीफ तथा स्तनपान के समय पसीना आने जैसे लक्षणों के आधार पर की गई।

राज्योत्सव 2025 : नवा रायपुर में होगा रोमांचक एयरशो, सूर्यकिरण टीम दिखाएगी हैरतअंगेज करतब

कलेक्टर ने शो की तैयारियों को लेकर स्थल का किया निरीक्षण

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम द्वारा प्रस्तावित भव्य एयरशो का आयोजन किया जाएगा। इससे एक दिन पहले 4 नवंबर को टीम द्वारा रिहर्सल किया जाएगा। आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह आयोजन प्रदेशवासियों के लिए रोमांच और गर्व से भर देने वाला अनुभव होगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर नम्रता जैन (आईएएस), जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एडीएम उमाशंकर बंदे तथा एएसपी विवेक शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को भेजी, ईडी या सीबीआई को सौंपने की तैयारी

एनएचएआई ने अफसरों भी मामले में शामिल

संवाददाता। भारतमाला परियोजना भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी जांच की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर के मुआवजा घोटाला मामले की प्रशासनिक व ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच हो चुकी है। जांच में राजस्व अधिकारियों को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही ईओडब्ल्यू-एसीबी ने एनएचएआई के तीन अधिकारियों की भी संलिप्तता मानकर प्रकरण तो दर्जकर लिया है, लेकिन जांच एजेंसी को एनएचएआई ने अफसरों के खिलाफकार्रवाई की अनुमति नहीं दी है।

एनएचएआई के मुताबिक जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रही है। ऐसे में एनएचएआई के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नहीं है। एनएचएआई के अफसरों का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार इस मुआवजा घोटाला प्रकरण को ईडी या सीबीआई को सौंप सकती है।

गौरतलब है कि ईडी ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले के संबंध में दर्ज एफआईआर व जांच प्रतिवेदन की जानकारी ईओडब्ल्यू से मांगी थी। मामले में ईडी की ओर से ईसीआईआर दर्ज की जा सकती है।

जानकारों का कहना है कि ये घोटाला शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें कुछ आईएएस के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। जमीन का आकार छोटा करके तीन से सात गुना तक ज्यादा मुआवजा सरकार से लेने से लेकर किसानों से जमीन खरीदकर उसे ज्यादा कीमत में बेचने समेत कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं।

क्या है मामला

रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर भू-अर्जन मुआवजा घोटाले में शासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद आर्थिक क्षति की राशि और बढ़ सकती है। जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर यह घोटाला किया गया है।

एनएचएआई टीम ने भी जताई थी आपत्ति

रायपुर विशाखापट्नम इकोनॉमिक कॉरिडोर में हुई आर्थिक गड़बड़ी पर एनएचएआई के अधिकारियों ने भी आपत्ति जताई थी। एनएचएआई की आपत्ति के बाद जांच रिपोर्ट को सचिव राजस्व विभाग को भेजा गया था और मुआवजा वितरण रोका गया था।

प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ के तहत शासकीय कर्मचारी बच्चों संग साझा कर रहे हैं खुशियाँ

बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, कर्मचारियों का जन्मदिन बना यादगार

रायपुर, संवाददाता

जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित ÷प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ÷ का उद्देश्य ही है – खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं। इसी क्रम में आज फार्मासिस्ट ग्रेड 2 श्री अविनाश शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 59 न्यू सुभाष नगर टिकरापारा, प्रधान पाठक श्रीमती चंद्ररेखा बांधे ने शासकीय प्राथमिक शाला भेलवाडीह अभनपुर, प्रधान पाठक श्री तुलचंद साहू ने शासकीय प्राथमिक शाला तेंदुआ अभनपुर में अपने जन्मदिन के अवसर पर नन्हे बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 23 कर्मचारियों को ई-कार्ड और एसएमएस के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित कर उन्हें सामाजिक सरोकार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

एआई टूल की मदद से स्टूडेंट ने बनाई ट्रिपल आईटी नया रायपुर की 36 छात्राओं की अश्लील फोटो, खुलासे के बाद हड़कंप

,संवाददाता। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी रायपुर में इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर छात्र पर संस्थान की 36 छात्राओं की अश्लील फोटो बनाने का आरोप लगा है. एआई की मदद से बनाए गए छात्राओं के फोटो के खुलासे के बाद से संस्थान में हड़कंप है। तलाशी के बाद आरोपी छात्र का लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त कर लिया है।

नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में इलेट्रानिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग का थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लैपटॉप से वहां पढ़ रहीं छात्राओं के 1000 से अधिक फोटो और वीडियो मिले है, जिसके बाद प्रबंधन ने आरोपी छात्र को संस्थान से निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर निवासी ट्रिपल आईटी रायपुर इंजीनियरिग छात्र की पीड़ित छात्राओं द्वारा की गई शिकायत पर संस्थान द्वारा आरोपी छात्र के कमरे की तलाशी ली गई और उसके लैपटॉप और फोन से छात्राओं के 1000 से अधिक फोटो और वीडियो बरामद किए। तलाशी के बाद छात्र का लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ता है छात्र ट्रिपल आईटी रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में तीसरे वर्ष के छात्र के लैपटॉप से बरामद हुए छात्राओं के अश्लील फोटो केस की जांच ट्रिपल आईटी की महिला स्टाफ कर रही है। मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है।

पुलिस में अब तक शिकायत नहीं

गौरतलब है संस्थान की छात्राओं की शिकायत पर महिला स्टाफद्वारा जब आरोपी छात्र के कमरे की तलाशी गई, तो उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से संस्थान की छात्राओं की हजारों फोटो और वीडियो मिले, जिसके बाद प्रबंधन ने उसके मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त कर लिया है।

संपादकीय

बिहार से शुरुआत हो

कई चरणों में मतदान आम चलन बना हुआ है। मगर साथ ही यह धारणा भी मजबूत हुई है कि इस तरह चुनाव को अत्यधिक खर्चीला बनाया गया है, जिससे कम संसाधन वाले दलों के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं। बिहार के राजनीतिक दलों में बनी यह सहमति महत्त्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक या अधिक से अधिक दो चरणों में कराया जाना चाहिए। निर्वाचन आयुक्तों के साथ बैठक में इन दलों ने यह राय दो-टूक लहजे में बताई। उनका यह तर्क गौरतलब है कि राज्य में ना तो कानून-व्यवस्था की कोई समस्या है और ना ही अब पहले जैसे नक्सल ग्रस्त इलाके हैं, जिन्हें तर्क बना कर अनेक चरणों में मतदान कराने की शुरुआत की गई थी। हालांकि 1990 के दशक में जब यह शुरुआत हुई, तब भी इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठे थे, लेकिन तब प्रभु वर्ग में बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर एक खास तरह का प्रतिक्रिया भाव था।

अकेला मनुष्य .

शहर बड़ा होता
सड़कें फैल रहीं
इमारतें आसमान की ओर,
मनुष्य जा रहा सिकुड़ता
अपने मोबाइल के स्क्रीन में
वह अब हँसता
पर चेहरा नहीं ,
भावनाएँ ÷इमोजी÷ में,
जहाँ आँसू भी
नीले गोले में समा गए ।
बच्चे अब मिट्टी में नहीं ,
बल्कि ÷एप्स÷ पर खेलते
सीखते पेड़ कैसे लगाएें।
माँ की रोटी की महक
अब ऑनलाइन डिलीवरी में ,
स्वाद पर अपनापन नहीं।

बुज़ुर्ग पार्क में बैठते ,
बतियाते नहीं,
बस स्वास्थ में
अपने कदम गिनने
किसी से मिलते,
संबंध ÷रीचार्ज÷ करवाते
मोबाइल और अपने धैर्य का।
और शहर –
हर पल भागता ,
किसी को पछाड़ना चाहता,
उसे यह नहीं मालूम
जिसे वह पछाड़ रहा
खुद उसका अपना साया ।

कभी-कभी कोई बच्चा
दीवार पर चॉक से कुछ लिख देता –
÷बड़ा होकर आदमी बनना चाहता हूँ।÷
लोग मुस्कुराते ,
अब ÷आदमी÷
पुराने ज़माने का शब्द ।
अब भी,
कहीं दूर किसी गाँव में
एक पेड़ खड़ा
जो किसी पहचान कर नहीं
पर सबको छाया देता
वह हमें बुलाता
÷लौटो, थोड़ी देर बैठो,
कुछ देर के लिए इंसान बनो।÷

- संजीव ठाकुर

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा
लिखित पुस्तकें पढ़िये
ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

मानसिक स्वास्थ्य है रोगमुक्त जीवन की मुस्कान

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष हमें यह सोचने का अवसर देता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका मन है, और जब मन अस्वस्थ होता है तो समूचा जीवन बिखर जाता है। इस वर्ष की थीम है संकट और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना। यह थीम प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, जो मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने और संकटग्रस्त लोगों के लिए प्रभावी सहायता तंत्र स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करती है। आज दुनिया ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही है जहाँ महामारी, युद्ध, आर्थिक संकट, सामाजिक अस्थिरता, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएँ लगातार मनुष्य के मन पर चोट कर रही हैं। इन आपदाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक मौन महामारी बन गई है। भारत में यह चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कम है और कलंक अधिक। मानसिक स्वास्थ्य दिवस सभी के लिए है-यह वर्ष के 365 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन 10 अक्टूबर दुनिया भर के सभी लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने हेतु एकजुट होने का एक अवसर है। यह सभी को अधिक समझ और सहानुभूति के माध्यम से अपने और दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आज का युग आभासी दुनिया का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल साधनों ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतना ही जटिल भी। आभासी संबंधों ने संवाद के नए मार्ग खोले हैं, परंतु भावनाओं की सच्चाई को खोखला कर दिया है। हम हर समय आभासी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत अकेले हो गए हैं। दूसरों के सुख और सफलता के प्रदर्शन से तुलना और हीनता की भावना बढ़ती जा रही है। इस निरंतर प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन ने लोगों के मन में चिंता, अवसाद और असंतोष को गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया का अति प्रयोग मनुष्य को कल्पना और भ्रम की दुनिया में धकेल रहा है, जहाँ असली जीवन की सादगी और आत्मीयता खोती जा रही है। युवा पीढ़ी सबसे अधिक मानसिक दबाव में है। प्रतिस्पर्धा, परीक्षा, करियर और परिवार की अपेक्षाएँ उन्हें उस स्तर तक पहुँचा रही हैं जहाँ असफलता आत्मघाती कदमों में बदलने लगी है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ी संख्या किशोरों और युवाओं की है। वे जीवन से नहीं, अपनी असफलता से भागना चाहते हैं, परंतु संवादहीनता, समझ की कमी और मानसिक परामर्श की अनुपलब्धता उन्हें अंधकार की ओर धकेल देती है। युवा जीवन में ऊर्जा और आशा के प्रतीक हैं, लेकिन जब उन पर अपेक्षाओं का बोझ हावी हो जाता है, तब वही ऊर्जा विनाशकारी रूप ले लेती है। परिवार और समाज को चाहिए कि वे उन्हें समझें, संवाद करें, उनके मन की सुनें, और उन्हें यह विश्वास दें कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर है। महिलाओं की स्थिति भी कम कठिन नहीं है। घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों, सामाजिक बंधनों और लैंगिक भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहरे रूप से प्रभावित किया है। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता की स्थितियाँ उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं। फिर भी वे समाज की धुरी बनी रहती हैं। उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना, उनके लिए सुरक्षित वातावरण और परामर्श की सुविधाएँ उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब महिलाएँ स्वस्थ और संतुलित मन से कार्य करेंगी, तभी समाज स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह वृद्धों का जीवन भी मानसिक स्वास्थ्य के मामले में अधिक जटिल होता जा रहा है। आत्महत्या की बढ़ती घटनाएँ एक चेतावनी हैं कि हम किसी बड़ी भूल के शिकार हैं। यह केवल व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्पण है। जब कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब उसकी आत्मा में आशा का दीप बुझ जाता है। उसे बचाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके पास जाएँ, उसकी बात सुनें, उसे यह एहसास दिलाएँ कि वह अकेला नहीं है। समाज, परिवार, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ निराश व्यक्ति के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध हो। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव-गाँव तक पहुँचें, स्कूलों और कार्यस्थलों में परामर्श केंद्र स्थापित हों, यह समय की पुकार है।

नशा मानसिक अस्वास्थ्य का सबसे बड़ा सहचर बन चुका है। शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, यहाँ तक कि दवाओं के दुरुपयोग ने मनुष्य की चेतना को कुंद कर दिया है। नशा अस्थायी आनंद देता है, परंतु दीर्घकालिक विनाश का कारण बनता है। यह व्यक्ति की आत्मनियंत्रण शक्ति को नष्ट कर देता है, निर्णय क्षमता को कमजोर करता है और अवसाद तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति समाज से कट जाता है और उसकी आत्मा में एक गहरा शून्य भर जाता है। इस समस्या का समाधान केवल दंड से नहीं, बल्कि संवेदनशील पुनर्वास और मानसिक परामर्श से संभव है। समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति शिक्षित करना और युवाओं को इसके जाल से बचाना हर घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता होती है आशा की। निराशा की अंधेरी सुरंग में यदि कोई हाथ थाम ले, यदि कोई मुस्कान दे दे, यदि कोई कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, तो वही वाक्य जीवनदान बन सकता है। आत्महत्या की रोकथाम का आरंभ संवेदनशील संवाद से होता है। हमें अपने बच्चों, मित्रों, सहकर्मियों और परिवारजनों से यह रिश्ता बनाना होगा कि वे अपने मन की बात कह सकें, बिना किसी भय या लज्जा के।

आज का हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। तनाव उनको होता है, जो निरंतर मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, विश्राम नहीं करते। यानी कि आज की भाषा में जो 'बिजी' रहते हैं। बिजी रहने की इस आदत ने जीवन में बहुत टेंशन पैदा किए हैं। जीवन में बिजी के साथ ईजी होना जरूरी है क्योंकि एक पहिए से रथ नहीं चलता। उसके लिए दोनों पहिए चाहिए। ज्ञान और ध्यान, काम और आराम- ये जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक पहिए को निकाल देंगे तो रथ नहीं चलेगा। आज यही तो समस्या है और यही मानसिक अस्वास्थ्य की जड़ है। जीवन को एकांगी बनाया जा रहा है। इससे बहुत भारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन की चंचलता का तो ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किया जा रहा है, पर उसे स्थिर बनाने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। समस्या स्थिरता में नहीं, चंचलता में होती है। बाहर का खोल जितना भी मजबूत हो, भीतर को साधे बिना चंचलता कम नहीं होती। ये भीतर की गांठें देर-सबेर उलझा ही देती हैं। आज आवश्यकता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता समझें। शरीर की बीमारी के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की पीड़ा के लिए भी विशेषज्ञ सहायता लेना सामान्य बने। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालयों में जोड़ा जाए, परामर्श केंद्रों को सशक्त किया जाए, और हर नागरिक को यह संदेश दिया जाए कि सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज का आधार है। हमें निराशा से आशा की ओर, अकेलेपन से अपनत्व की ओर और अस्वस्थता से संतुलन की ओर बढ़ना है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है, और जब मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होगा, तभी जीवन भी सुंदर होगा। इसलिए आइए, हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने और दूसरों के मन की सेहत का ध्यान रखेंगे, संवाद करेंगे, सहयोग करेंगे और हर उस व्यक्ति के लिए आशा का दीप जलाएँगे जो अंधेरे में भटक रहा है। यही इस दिवस का सच्चा संदेश और जीवन का शाश्वत सार है।

यह निजी विचार है।

देश की जनसंख्या प्रगति का पैमाना या अवरोध की अवधारणा

संजीव ठाकुर, लेखक, चिंतक, स्तंभकार

भारत की जनसंख्या अब मात्र एक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक चुनौती और अवसर दोनों का प्रतीक बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत ने लगभग 142.86 करोड़ (1.4286 अरब) की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने का गौरव प्राप्त किया। लेकिन यह उपलब्धि जितनी गौरवशाली है, उतनी ही चिंताजनक भी। जनसंख्या वृद्धि दर अभी लगभग 0.81 त्न है और कुल उर्वरता दर 2.0 पर स्थिर हो गई है, जो प्रतिस्थापन दर (2.1) के करीब है। भारत की लगभग 68 त्न आबादी कार्यशील आयु वर्ग (15ङ्क64 वर्ष) में है, जो विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति का निर्माण करती है। यह स्थिति भारत के लिए ÷जनसंख्या लाभांश÷ का अवसर प्रस्तुत करती है, बशर्ते कि इसे शिक्षा, कौशल और रोजगार की दिशा दी जाए। यदि यह जनसंख्या शिक्षित, प्रशिक्षित और उत्पादक बनी तो यही भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकती है, परंतु यदि यही जनसंख्या बेरोज़गारी, अशिक्षा और संसाधनों के अभाव में उलझी रही, तो यही राष्ट्र के लिए बोझ भी बन सकती है।

नंतभारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रत्येक वर्ष लाखों युवक श्रमबाज़ार में प्रवेश करते हैं, परंतु उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बन पाते। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण (क्क्रस्न्र) 2023-24 के अनुसार 15 वर्ष से ऊपर की आबादी में बेरोज़गारी दर 3.2 त्न रही, जबकि युवाओं (15ङ्क29 वर्ष) में यह बढ़कर 10.2 त्न तक जा पहुँची। कार्यशील आयु वर्ग में लगभग 64.33 करोड़ लोग हैं, परंतु संगठित क्षेत्र में उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा। उदाहरण के तौर पर किसी ग्रामीण क्षेत्र के दस हज़ार युवा जब शहरों की ओर रोज़गार की तलाश में जाते हैं, तो उनमें से मुश्किल से दो हज़ार को ही अस्थायी या कम वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। शेष बेरोज़गार या असंगठित क्षेत्र में अल्प आय पर कार्यरत रह जाते हैं। परिणामस्वरूप गरीबी, कुपोषण और सामाजिक तनाव की स्थिति बढ़ती है, जो राष्ट्र की विकास गति को धीमा करती है।

।भारत की विशाल जनसंख्या के कारण जल, भूमि, ऊर्जा और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर असंतुलित दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ इनका अति-दोहन जल संकट, भूमि क्षरण और ऊर्जा की कमी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है। महानगरों में रोजगार की तलाश में पलायन से झुग्गी-झोपड़ियाँ फैल रही हैं, यातायात और प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है तथा जीवन स्तर गिरता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है – प्रदूषण, वनों की कटाई, कचरे का बढ़ता ढेर और ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन अब चिंता का वैश्विक विषय बन चुका है। जब समाज का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष, असुरक्षा और अपराध में वृद्धि होती है, जिससे सामाजिक समरसता कमजोर पड़ती है।

चीन ने इस समस्या के समाधान के लिए ÷वन चाइल्ड पॉलिसी÷ जैसी कठोर नीति अपनाई थी, जबकि भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप परिवार नियोजन, जागरूकता और स्वैच्छिक नियंत्रण की नीति को अपनाया। किंतु ग्रामीण और अशिक्षित क्षेत्रों में अब भी पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा, सबसे प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है। एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं जागरूक होती है बल्कि पूरे परिवार को सही दिशा देती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास अभियान, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाएँ युवाओं को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि इन योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचे तो रोजगार सृजन की प्रक्रिया तीव्र हो सकती है।

भारत में विकास को संतुलित बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे पलायन पर नियंत्रण हो सके और शहरी क्षेत्रों पर बढ़ता बोझ घटे। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार कर मातृ-शिशु मृत्यु दर घटानी होगी। वर्ष 2024 में भारत की मातृ मृत्यु दर अब भी 97 प्रति एक लाख जीवित जन्म है और शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार के आसपास है। इन आंकड़ों में सुधार किए बिना ÷स्वस्थ भारत÷ का सपना अधूरा रहेगा।

जनसंख्या की समस्या केवल संख्याओं की नहीं बल्कि गुणवत्ता की समस्या है। एक शिक्षित, स्वस्थ और रोजगारयुक्त जनसंख्या ही राष्ट्र के विकास की गति को तीव्र कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या को केवल बोझ न समझा जाए, बल्कि अवसर के रूप में देखा जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनसंख्या नियंत्रण की एकीकृत नीति ही इस अवसर को शक्ति में बदल सकती है।

भारत की यह जनसंख्या वास्तव में एक दोधारी तलवार है – यदि इसे दिशा, दृष्टि और अवसर मिले तो यही भारत को विश्वशक्ति बना सकती है; और यदि यह अनियंत्रित रही तो यही देश की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम ÷संख्या की भीड़÷ को ÷सक्षम शक्ति÷ में परिवर्तित करें। तभी यह भूमि अपने जनसमुदाय के भार से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से आलोकित होगी – और भारत अपने जनबल से जगत में ÷विकासशील÷ से ÷विकसित राष्ट्र÷ बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

एसआईआर के कई सवाल अब भी अनसुलझे

अजीत द्विवेदी

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें करीब सात करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या सात करोड़ 89 लाख थी, जो अब घट कर सात करोड़ 42 लाख हो गई है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिर्फ 47 लाख नाम घटे हैं। लेकिन असल में करीब 69 लाख नाम कटे हैं। यह सात करोड़ 42 लाख की जो संख्या दिख रही है उसमें साढ़े 21 लाख नाम ऐसे हैं, जो नए जोड़े गए हैं। सो, चुनाव आयोग ने अपनी ओर से एसआईआर का काम पूरा कर दिया है। अगले कुछ दिन में एक पूरक सूची आ सकती है, जिसमें कुछ और नए नाम होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से सारे सवालों के जवाब मिल गए? इसको लेकर जितने संदेह थे, सब दूर हो गए? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा मामला बंद हो जाएगा या वहां नए सवाल खड़े होंगे?

ध्यान रहे एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च अदालत ने मतदाता के सत्यापन के एक दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल करने और जिन लोगों के नाम कटे थे उनके ऑनलाइन आवेदन लेने का जिस दिन आदेश दिया था उस दिन कहा था कि अगर गड़बड़ी मिली तो वह पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगी। पता नहीं अदालत की आगे की सुनवाई में क्या होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अनेक सवाल अनसुलझे रह गए हैं। इनका जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक इसका विरोध तेज हो गया है। केरल में तो विधानसभा में सर्वसम्मति से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। सो, कह सकते हैं कि एसआईआर की एक परीक्षा अभी और होनी है।

बहरहाल, अब बिहार के एसआईआर के आंकड़े को देखने और उसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने जुलाई के अंत में जो मसौदा सूची जारी की थी उसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख 64 हजार नाम काट दिए गए थे। उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ लेकिन आयोग अपनी बात पर अड़ा रहा। आयोग ने कहा कि इसमें 22 लाख से कुछ ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनका निधन हो गया है, 36 लाख से कुछ ज्यादा लोग स्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं और साढ़े छह लाख के करीब लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर थे। यह हिसाब था 65 लाख 64 हजार लोगों के नाम कटने का। अब नाम कटने का आंकड़ा 69 लाख का है। सवाल है कि साढ़े तीन लाख के करीब जो नए नाम कटे हैं, वह किन लोगों के हैं? चुनाव आयोग ने इनको नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में रखा था और नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने खुद ही बताया है कि बिना पक्ष सुने किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। सो, जाहिर है कि इन साढ़े तीन लाख लोगों का पक्ष सुन कर इनका नाम काटा गया होगा। तो अब सवाल है कि इनके दस्तावेजों में क्या गड़बड़ी थी? क्या इनके पास आधार भी नहीं था? या आधार था लेकिन आयोग को उसकी प्रामाणिकता पर संदेह था?

ध्यान रहे अनेक लोगों की कहानियां आ रही हैं कि उनके पास सिर्फ आधार था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दम पर वे आधार के जरिए मतदाता बन गए। अगर साढ़े तीन लाख लोगों के पास आधार भी नहीं था या आधार था तो संदिग्ध था तो चुनाव आयोग ने उनका क्या किया? क्या आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई जानकारी भेजी है? क्या उसने इन लोगों को संदिग्ध नागरिक की श्रेणी में रखा है? अगर ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा और नोटिस आने के बाद गायब हो गए तो उनकी भी जानकारी निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय की दी जानी चाहिए, क्या आयोग ने ऐसा किया है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं अन्यथा आगे जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां भी मसौदा सूची में नाम होने के बावजूद लाखों लोगों के नाम अंतिम सूची से बाहर हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार में जिन साढ़े तीन लाख लोगों के नाम मसौदा सूची में होने के बावजूद कटे हैं या तो वे विदेशी व संदिग्ध नागरिक हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं या इसी देश के नागरिक हैं लेकिन किसी तकनीकी आधार पर उनका नाम काट कर उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? ये दोनों स्थितियां चिंताजनक हैं।

इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार को किस रूप में लिया? अगर किसी नागरिक की ओर से एकमात्र पहचान पत्र के तौर पर आधार पेश किया गया तो उसे आयोग ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया या संदिग्ध बता कर किसी और दस्तावेज की मांग की गई? इस सवाल का जवाब भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां ज्यादातर लोग आधार ही पेश करेंगे। इसके अलावा एक सवाल यह है कि मसौदा सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग के सामने जो दावे और आपत्तियां आई थीं उनमें से कितने को और कैसे निपटाया गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुकदमा लड़ने वाले लोग बता रहे हैं कि आयोग के सामने जो आपत्तियां आई थीं उनमें 57 फीसदी ऐसी थीं, जिसमें लोगों ने अपना नाम काटने को कहा था।

यह निजी विचार है।

देश में वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य और ई-ऑफिस, भविष्य और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा विषय पर साइबर स्वच्छता कार्यशाला में

पीआईबी

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई), विनय मार्ग, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना से प्रेरित थी। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहलों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक ई-गवर्नेंस प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत साइबर बुनियादी प्रणाली की आवश्यकता पर बल देना था।

कार्यशाला का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव के स्वागत भाषण एवं संदर्भ निर्धारण के साथ हुआ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित साइबर स्वच्छता कार्यशाला में अपने संबोधन में आज की डिजिटल दुनिया में डेटा के ज़िम्मेदार और विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तियों और संगठनों के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो एक स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित साइबर वातावरण सुनिश्चित करती हैं जिससे समुचित डिजिटल लचीलापन और ऑनलाइन प्रणालियों में विश्वास मज़बूत होता है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने सीईआरटी-इन द्वारा साइबर लचीलेपन के लिए की गई पहलों पर चर्चा की और साइबर लचीलेपन की अवधारणा को साइबर खतरों के जवाब में पूर्वानुमान लगाने, उनका सामना करने, उनसे उबरने और विकसित होने की क्षमता के रूप में विस्तार से बताया।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने ई-ऑफिस एनालिटिक्स के उपयोग और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वीपीएन के उपयोग की समीक्षा करने, प्रत्येक स्तर पर गैर-उपयोगकर्ताओं की पहचान करने और उचित सत्यापन के बाद निष्क्रिय खातों को निष्क्रिय करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागों से आंशिक फाइलों के प्रसार से बचने और ई-फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की प्रणाली विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने ई-ऑफिस के कुशल संचालन के लिए चार का औसत विशिष्ट स्तर बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

सीईआरटी-इन के वैज्ञानिक-जी श्री एसएस शर्मा ने सरल लेकिन प्रभावी साइबर स्वच्छता प्रणाली जैसे सुरक्षित पासवर्ड बनाए रखना, क्लिक करने से पहले लिंक की प्रामाणिकता की पुष्टि करना और वेबसाइटों के सुरक्षा प्रमाणपत्रों की जांच करना आदि पर चर्चा की।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वैज्ञानिक-जी सुश्री अंजलि ढींगरा ने ई-ऑफिस में एप्लीकेशन सुरक्षा पर चर्चा की तथा सिस्टम और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्तरित सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, मजबूत प्रमाणीकरण और निगरानी उपायों पर प्रकाश डाला।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) श्री अनिल बंसल ने भविष्य पोर्टल पर चर्चा की जो केंद्रीय मंत्रालयों में पारदर्शी, जवाबदेह और समय पर पेंशन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल 99 मंत्रालयों, 1,037 कार्यालयों और 9,590 डीडीओ को कवर करता है, लगभग 3 लाख पीपीओ जारी करता है और एनईएसडीए 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता किट और आयुष्मान कार्ड का वितरण

पीआईबी। गोवा के पणजी में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता इको-सिस्टम कार्य (नमस्ते) योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) और कचरा बीनने वालों को पीपीई किट का वितरण

सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) और कचरा बीनने वालों को आयुष्मान कार्ड का वितरण

ईआरएसयू के लिए सुरक्षा उपकरणों का वितरण नमस्ते योजना पर एक पोशाक-आधारित कार्यक्रम (फैशन शो) केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता इको-सिस्टम कार्य (नमस्ते) योजना के बारे में जानकारी साझा की जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 90,494 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है, 84,077 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की जा चुकी है और 68,341 कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

पोषण माह 2025 समारोह के दौरान पुडुचेरी में वृक्षारोपण कार्यकलाप आयोजित किए गए

पोषण माह 2025 समारोह के दौरान पुडुचेरी में वृक्षारोपण कार्यकलाप आयोजित किए गए। इस पहल ने अच्छे पोषण, टिकाऊ जीवन और सामुदायिक कल्याण के बीच संबंधों को रेखांकित करते हुए स्थानीय लोगों को एक स्वस्थ और हरित भविष्य के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।

एआई-आधारित डिजिटल प्रणालियां भारत की संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और समावेशी बना रही हैं: लोकसभा अध्यक्ष

एजेंसी। संसद भाषिणी÷ जैसी रियल-टाइम एआई अनुवाद प्रणालियां संसद के प्रत्येक सदस्य को निकट भविष्य में अपनी भाषा में संवाद करने की अनुमति देंगी: लोकसभा अध्यक्ष

लोकतंत्र तब सबसे मजबूत होता है जब नागरिक अपनी संसद के साथ गहराई से जुड़े होते हैं: लोकसभा अध्यक्ष

भारतीय संसद की ई-संसद तक की यात्रा अपनी पहुंच और कार्यप्रणाली के संदर्भ में काफी अभूतपूर्व रही है: लोकसभा अध्यक्ष

÷संसद÷ पहल के अंतर्गत भारत की संसद ने एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया है: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में कार्यशाला की अध्यक्षता की

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों से आग्रह किया है कि वे प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटते हुए एआई के ज़िम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा दें। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में 'प्रौद्योगिकी का लाभ: डिजिटल परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देना और डिजिटल विभाजन को दूर करना' विषय पर एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए श्री बिरला ने कहा कि सहयोग और ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी एक सेतु बने, न कि एक बाधा।

उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति और ई-संसद के अनुप्रयोग ने हमारे संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में बड़े परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। ई-संसद, ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है। श्री बिरला ने कहा कि एआई-आधारित डिजिटल प्रणालियां भारत की संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और समावेशी बना रही हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि एआई-आधारित अनुवाद, एआई-सक्षम ई-लाइब्रेरी और स्पीच-टू-टेक्स्ट रिपोर्टिंग जैसी प्रणालियां संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और समावेशी बना रही हैं। आगामी डिजिटल पहलों के बारे में श्री बिरला ने कहा कि जल्द ही 'संसद भाषिणी' जैसी रीयल-टाइम एआई अनुवाद प्रणालियां प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी भाषा में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेंगी - जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र के लिए एक नई ऊंचाई होगी।

(07कैप्शन18)तमिलनाडु में 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (एनओएसडीसीपी) के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास (एनएटीपीओएलआरईएक्स-एक्स) के 10वें संस्करण की बैठकें। आईसीजी के महानिदेशक श्री परमेश शिवमणि ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

(08कैप्शन10)केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री , श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2025 के दौरान राष्ट्रीय संचार अकादमी और एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के साक्षी बने।

भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा

24,634 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी

पीआईबी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपये के परिव्यय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें: महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन और, मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों में व्याप्त इन चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है, तथा दो आकांक्षी जिलों, विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा।

लाइन क्षमता में बढ़ोत्तरी से गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी ट्रैकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) प्रस्ताव परिचालन सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए भी आवश्यक मार्ग है। पटरियों की संख्या बढ़ाए जाने से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।

रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह देश के जलवायु लक्ष्यों और परिचालन लागत कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) में कमी लाने और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

सेवा पखवाड़ा में मड़वा विद्युत संयंत्र ने रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता कार्य एवं मैराथन दौड़ का किया आयोजन

जांजगीर चांपा - अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र (एबीवीटीपीएस) मडवा में जनसेवा का पर्व सेवा पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम शासन के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विद्युत संयंत्र एवं आसपास के गांवों में आयोजित किए गए। जन-जागरूकता एवं सेवा कार्य के लिए रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान एवं मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। सेवा पखवाडा का शुभारंभ 17 सितंबर को विद्युत संयंत्र के तकनीकी भवन सभागार में मुख्य अभियंता श्री एचएन कोसरिया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा की जानकारियां कर्मचारी, अधिकारी एवं श्रमिकों के बीच साझा की गई। 18 सितंबर को जिला चिकित्सालय, जांजगीर के सहयोग से पॉवर जनरेशन कंपनी के विभागीय अस्पताल मड़वा मे रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 36 व्यक्तियों ने रक्तदान कर जनजागरूकता की मिसाल कायम की। 22 से 24 सितंबर के बीच ग्राम मड़वा, तेंदूभाठा एवं औराईकला में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। तेन्दूभाठा में 95, मड़वा में 109 एवं औराईकला में 130 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांचकर उन्हें दवाइयां बांटी गईं। स्वास्थ्य शिविर के संचालन एवं समन्वय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके. साहू, चिकित्सा अधिकारी डा. विकेन्द्र सिंह एवं विभागीय अस्पताल की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

24 सितंबर को विद्युतनगर आवासीय परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सफाई करते हुए श्रमदान किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री एचएन. कोसरिया द्वारा स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सफाई कर्मियों को उनके निरंतर सहयोग के लिए मुख्य अभियंता के हाथों सम्मानित भी किया गया। 28 सितंबर को विद्युतनगर आवासीय परिसर मार्ग पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक, महिलाओं एवं बच्चों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मैराथन दौड़ में रूद्र कंवर को प्रथम स्थान, दिलीप तिग्गा को द्वितीय एवं पवन मेहरा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अभियंता के हाथों पुरस्कृत किया गया। मैराथन का आयोजन क्षेत्रीय क्रीड़ा सचिव किशोर कुमार टोप्पो, सहसचिव दिनेश मेश्राम एवं सहायक प्रबंधक (पर्यावरण) संजय कुमार झा के समन्वय एवं सहयोग से किया गया। सेवा पर्व पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता ए.के.साह, एसडी, द्विवेदी, आरएल. ध्रुव, आरके. साव एवं एन.लकरा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया।

जिले की सबरिया समाज के लोगों की स्वरोजगार के लिए पुलिस अधीक्षक की पहल

आगामी 11 अक्टूबर को कोड़केल गेंदा महोत्सव में शामिल हो सीखेंगे गेंदा खेती के गुर

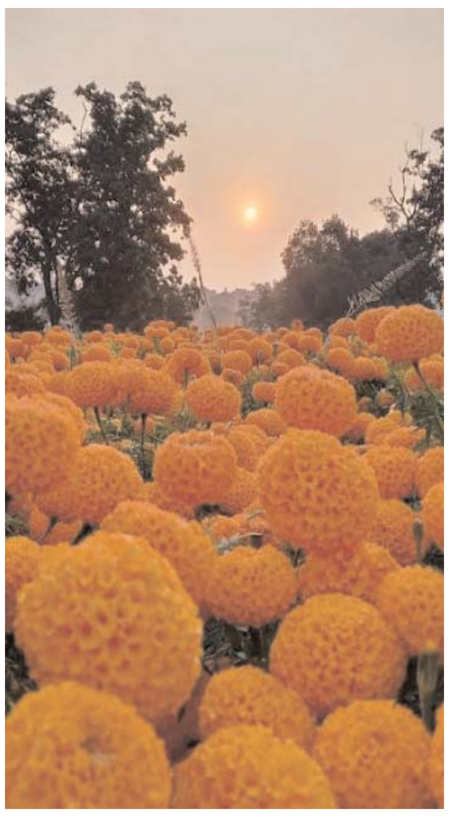

जांजगीर चांपा संवाददाता / पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस की पहल का असर अब जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सामाजिक पुलिसिंग के अंतर्गत सबरिया समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्वयं सबरिया समाज के लोग अब अवैध शराब बिक्री से दूरी बनाने का संकल्प ले रहे हैं, और स्वरोजगार का राह अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा द्वारा समाज के लोगों को स्वरोजगार, कौशल विकास और विशेष प्रशिक्षण के लिए दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को गेंदा महोत्सव लैलूंगा रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सबरिया समुदाय के लोगों को शामिल कराएंगे जिनको गेंदा खेती करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत जिले में आकर अपना गेंदा खेती कर आत्म निर्भर बनेंगे। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि यदि समाज का कमजोर वर्ग आत्मनिर्भर होगा तो वह किसी भी तरह के अवैध कार्यों में शामिल नहीं होगा। पुलिस का यह कदम जिले के लिए मिसाल बनता

मारपीट कर चाकू से हमला करने के आरोपी को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांजगीर चांपा / मारपीट कर चाकु से हमला के आरोपी को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है । मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 8 अक्टूबर की रात्री करीब 11:30 बजे आहत आकाश यादव को आरोपी द्वारा अश्लील गाली गलौच करने लगा और पुराने केश को वापस करने की बात बोला , तब आकाश यादव के द्वारा केश वापस नहीं लूंगा बोला तो शिवम यादव के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया था । इसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना दौरान थाना जांजगीर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी जांजगीर, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, प्रकाश राठौर, राकेश तिवारी, आरक्षक दिलीप सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

रात्रि में युवक का रास्ता रोककर स्कूटी लूट के फरार दो आरोपियों को मुलमुला पुलिस ने पकड़ा

जांजगीर चांपा / रात्री में रास्ता रोककर स्कूटी लूट के फरार दो आरोपियों को मुलमुला पुलिस ने पकड़ा है । पकड़े गए आरोपीयों में राहुल उर्फ पुष्पराज गुप्ता उम्र 20 वर्ष , पिंटू उर्फ विशाल सिदार उम्र 20 वर्ष दोनो निवासी कोसा थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा शामिल है। मामले का विवरण में प्रार्थी आदित्य पाटले निवासी भगवानपाली थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 2 अक्टूबर 2025 को वह अपनी स्कूटी से शिवरीनारायण दशहरा और नवरात्रि मेला देखने आया था जो स्कूटी से अपने घर जा रहा था। रात्रि करीबन 11.30 बजे कोसा मेन रोड पर पहुंचा, तो आरोपियों ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कर स्कूटी को लूट कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए और मौके से फरार हो गए जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 317/25 पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों रायपुर तरफ होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी मुलमुला निरी. पारस पटेल, सउनि प्रमोद महार, प्र.आर. राजमणी द्विवेदी, प्र.आर. बलबीर सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

रेत खदानों के ई-नीलामी प्रक्रिया संबंधी कार्यशाला 13 अक्टूबर को

जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खनिज रेत हेतु नई नीति छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 लागू की गई है। इस नियम के तहत गौण खनिज साधारण रेत खदानों का आबंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल के जरिए किया जाना है। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया जैसे निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने हेतु बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी, बोलीकर्ता का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि सभी कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। खनि अधिकारी ने बताया कि गौण खनिज साधारण रेत खदानों के आबंटन हेतु ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अंतर्गत एमएसटीसी पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में जारी निविदा, टेंडर का अवलोकन, बोली प्रतिभूति देखने, इच्छुक बोलीदारों द्वारा पोर्टल में पंजीयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा करने आदि से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण, कार्यशाला कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर के प्रार्थना सभा कक्ष में 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ता इसमें शामिल हो सकते है ।

अनुपूरक सूचियों का मुद्रण कार्य किये जाने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार फ ोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 33-अकलतरा, 34-जांजगीर-चांपा, 35-सक्ती (आंशिक), 37-जैजैपुर (आंशिक) एवं 38 पामगढ़ (अ.जा.) अंतर्गत कुल 1006 मतदान केन्द्रों के फोटोयुक्त/फोटोरहित निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) यथा मदर रोल एवं आयोग के निर्देशानुसार अनुपूरक सूचियों का मुद्रण कार्य किये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्य फर्मों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है।

25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, रायपुर संभाग ने जीता ओवरऑल चौम्पियन का खिताब

युवा पहलवानों ने दिखाया दमखम

जांजगीर-चांपा / शासकीय हाईस्कूल मैदान, जांजगीर में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभागों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुश्ती फ्रीस्टाइल बालक-बालिका में 14, 17, 19 वर्ष तथा कुश्ती ग्रीको रोमन बालक में 17 और 19 वर्ष वर्ग के मुकाबले आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित किया।

समापन समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गढेवाल, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला उपाध्यक्ष श्री मोहन यादव, जिला पंचायत सदस्य सुश्री आशा साव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रियंका सिंह क्षत्री, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रमिला साहू, श्री अमर सुलतानिया, श्री विवेका गोपाल, श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, पार्षदगण, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक सिन्हा, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने विभिन्न वर्गों में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो से सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन भी किया।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने अपने संबोधन में जाज्वल्यदेव की नगरी में आयोजित इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता को गौरवमयी बताते हुए कहा कि कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों में भारत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले गुरु हनुमान और दारा सिंह जैसे महापुरुषों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को अपने गुरु से अनुशासन सीखना चाहिए और खेल की बारीकियों को समझकर अभ्यास करना चाहिए। खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अनुशासन भी सिखाता है। जीवन में अगर लक्ष्य तय कर लिया जाए और उस दिशा में ईमानदारी से परिश्रम किया जाए, तो सफलता निश्चित है। आप सभी युवा खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन करें यही हमारी शुभकामना है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी ने 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि खेल हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे खेलते हैं, तो उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। खेलों से जीवन में निष्ठा, समर्पण और सहयोग की भावना आती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों प्रोत्साहित किया कि वे पूरे समर्पण के साथ अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करें और जिला, राज्य एवं देश का नाम रोशन करें। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया ने खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि खेल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में। उन्होंने कहा की पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। जो विद्यार्थी खेल के साथ संतुलन बनाना सीखते हैं, वे जीवन में हर क्षेत्र में सफल होते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और भी बेहतर प्रदर्शन करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। नगर पालिका जांजगीर-नैला अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गढेवाल ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा की आप सभी युवा खिलाड़ी हमारे समाज की ऊर्जा और प्रेरणा हैं। आपमें जो जोश और प्रतिभा है, वह आने वाले समय में आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर आपने खेल भावना का परिचय दिया है।

प्रतियोगिता में रायपुर संभाग रहा ओवरऑल चौंपियन - प्रतियोगिता में रायपुर ओवरऑल चौंपियन रहा। इसी प्रकार कुश्ती बालक 14 वर्ष में रायपुर प्रथम, द्वितीय- बिलासपुर, दुर्ग तृतीय, कुश्ती बालिका 14 वर्ष में प्रथम बस्तर, द्वितीय बिलासपुर, तृतीय सुरगुजा, कुश्ती बालक 17 वर्ष में प्रथम रायपुर, द्वितीय दुर्ग, तृतीय-बिलासपुर, कुश्ती बालिका 17 वर्ष में प्रथम रायपुर, द्वितीय बिलासपुर, तृतीय बस्तर, कुश्ती बालक 19 वर्ष में प्रथम रायपुर, द्वितीय बिलासपुर, तृतीय सरगुजा, कुश्ती बालिका 19 वर्ष में प्रथम बस्तर, द्वित्तीय रायपुर, तृतीय बिलासपुर, कुश्ती बालक 17 वर्ष ग्रीको रोमन में प्रथम बिलासपुर, द्वितीय दुर्ग, तृतीय रायपुर, कुश्ती बालक 19 वर्ष ग्रीको रोमन में प्रथम दुर्ग, द्वितीय बिलासपुर, तृतीय सरगुजा रहा।

राशनकार्ड घर बैठे कर सकते हैं ई-केवाईसी, अब नहीं जाना पड़ेगा राशन दुकान

जांजगीर-चांपा / शासन द्वारा राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब हितग्राहियों को ई-केवाईसी के लिए राशन दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य घर बैठे मोबाइल फोन से किया जा सकता है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल एप मेरा ई-केवायसी राशन कार्ड (httpsÑ//play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.facialauth) को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उक्त एप के माध्यम से सभी राशनकार्डधारी हितग्राही आधार फेस रिकग्निशन के जरिए अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं।

ई-केवाईसी प्रक्रिया -

एप इंस्टॉल करने के बाद राज्य का चयन करें, मोबाइल का लोकेशन ऑन करें। आधार नंबर दर्ज करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। कैप्चा भरने के बाद कार्ड विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद फेस ईकेवायसी के विकल्प पर क्लिक करें, कैमरा ऑन होते ही चेहरे को कैमरे के सामने रखें। चेहरा मैच होते ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक है। जिला खाद्य अधिकारी सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करें, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

खास खबर

अवैध रूप से राखड़ डंपिंग, भारतीय युवा कांग्रेस ने शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की

कोरबा, संवाददाता। तहसील पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में शंकर ट्रांसपोर्ट द्वारा अवैध रूप से राखड़ डंपिंग किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भारतीय युवा कांग्रेस के विधानसभा पाली-तानाखार अध्यक्ष अंकित सिंह पाल ने अनुविभागीय अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा को शिकायत पत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि ग्राम पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के चीर घर और टोनी ढाबा के समीप शंकर ट्रांसपोर्ट द्वारा नियमों को दरकिनार कर राखड़ डंप किया जा रहा है। डंपिंग स्थल के पास ही नाला है, जिसका पानी ग्रामीण दैनिक उपयोग में लाते हैं। ऐसे में राखड़ गिरने से जलस्रोत दूषित होने का खतरा है। वहीं राखड़ उड़ने से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है और राखड़ सड़क (छ-130) पर फैलने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। अंकित सिंह पाल ने कहा कि यदि सात दिनों के भीतर राखड़ डंपिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और संबंधित परिवहनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो भारतीय युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खिड़की पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटकी मिली महिला की लाश

कोरबा, दर्री स्थित पुष्प पक्षत्र कॉलोनी में एक कामकाजी महिला मंजू राव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर की खिड़की से लटका मिला। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, मंजू राव का शव चुनरी के सहारे लटका हुआ था। उनके पति सुनील राव ने बताया कि रात को खाने के बाद सभी सो गए थे। बाद में उन्हें पत्नी के आत्महत्या करने की जानकारी मिली। जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पड़ोसियों को सूचित किया। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पति ने कहा कि उनके बीच सब ठीक था कोई विवाद नहीं था। वहीं मायके वालों ने भी कहा कि शादी के बाद से सब ठीक था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पति ने कहा कोई विवाद नहीं सुनील राव ने अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह के विवाद या अन्य घटना से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि मंजू दुकान में काम करने जाती थीं। काम से लौटने के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया। सुनील टीवी देख रहे थे, जबकि मंजू बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब सुनील ने कमरे में जाकर देखा, तो यह घटना सामने आई। मायके वालों ने कहा-शादी के बाद कोई समस्या नहीं थी मंजू द्वारा उठाए गए इस कदम की जानकारी रात में ही खरसिया स्थित उनके परिजनों को मिल गई थी, जिसके बाद वे कोरबा पहुंचे। मंजू की मां बिसुन भट्ट ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2007 में हुई थी और तब से कोई समस्या सामने नहीं आई थी।

विकास कार्यों को मिला नया आयाम, रामपुर विधानसभा क्षेत्र की बढ़ेगी पहचान

रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफसे 186 करोड़ 90 लाख रूपये से अधिक के 640 कार्यों की मिली है स्वीकृति

o सड़क, नवीन स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन,स्वास्थ्य केन्द्र आदि से बनेगी नई पहचान

o वनांचल सहित आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को मिलेगी सुविधाएं

o 15 करोड़ 67 लाख की लागत से 134 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति

o 60 प्राथमिक षाला, 32 माध्यमिक षाला, 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन की स्वीकृति

o कुदमुरा से चिर्रा-ष्याांग मार्ग, अमलडीहा से मालीकछार मार्ग, 80 सीसी रोड़ निर्माण की मिली स्वीकृति

55 पीडीएस सह दुकान निर्माण, 19 पंचायत भवन, 27 स्वास्थ्य केन्द्रों में नवीन भवन एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति

कोरबा संवाददाता। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक अलग पहचान है। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकांश गांव में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र और करतला ब्लॉक के गाँव सम्मिलित है। दशकों से इस विधानसभा अंतर्गत अनेक गांवों में विकास की दरकार थी।

सड़क,स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड़,उपार्जन केंद्र गोदाम निर्माण,पंचायत भवन सहित कई ऐसी मांगे थीं, जो ग्रामीणों के लिए जरूरी होने के साथ ही उन्हें विकास की राह में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी था। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से आई मांगों के आधार पर यहाँ न सिर्फकार्यों की स्वीकृति मिली। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्यों को पूरा करने की दिशा में भी सतत प्रयास किया गया। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और शासन के निर्देश पर जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से 640 कार्यों के लिए 186 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। विगत डेढ़ वर्ष के मध्य रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत होने से जहाँ कई दशकों से बहुप्रतीक्षित चिर्रा-श्यांग की माँग पूरी होगी वहीं वनांचल के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सड़क मिल पायेगा। 86 सीसी रोड निर्माण, 134 नए आंगनबाड़ी भवन, 60 नवीन प्राथमिक शाला भवन, 32 नवीन माध्यमिक शाला भवन, 11 हायर सेकंडरी स्कूल हेतु नवीन भवन, 27 स्वास्थ्य केंद्रों में नवीन भवन,आवासीय भवन, अहाता निर्माण, 33 स्कूलों में अहाता निर्माण, 55 पीडीएस सह गोदाम निर्माण, 19 नवीन पंचायत भवन, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासीय भवनों का निर्माण, 11 उपार्जन केंद्रों में 150 मैट्रिक टन का गोदाम निर्माण, छात्रावास भवन सहित अतरिक्त कक्ष, शिक्षकों के ठहरने के लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल, अधीक्षक आवास, धान चबूतरा निर्माण सहित अन्य बड़े कार्य शामिल है। इसके साथ ही झगरहा-कोरकोमा-पसरखेत-चचिया मार्ग,भालूसटका-रिसदी बायपास मार्ग, सीलीभूडू-कुदरीचिंगार मार्ग का मजबूतीकरण, उन्नतिकरण, सुदूरवर्ती ग्राम अमलडीहा से मालीकछार तक सड़क, गिधौरी चारपारा मार्ग में पुलिया निर्माण, ओझायाइन से रामपुर तक पहुँच मार्ग सहित अन्य मार्गो के लिए भी डीएमएफ से राशि स्वीकृत कर अजीत वसंत कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास ने कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की राह में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

डीएमएफ से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत डेढ़ वर्ष में 186 करोड़ 90 लाख 24 हजार 643 रूपये की लागत से 634 विभिन्न कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें नौ करोड़ 35 लाख 44 हजार रूपये की लागत से कुदमुरा से श्यांग मार्ग का निर्माण कार्य, दो करोड़ 59 लाख 81 हजार रूपये की लागत से ग्राम अमलडीहा से मालीकछार पहूंच मार्ग निर्माण कार्य, दो करोड़ 86 लाख 58 हजार रूपये की लागत से ग्राम अमलडीहा से मालीकछार सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य, एक करोड़ 51 लाख 75 हजार 200 रूपये की लागत से विकासखण्ड कोरबा में छात्र-छात्राओं को पौष्टिक नाश्ता, एक करोड़ 59 लाख 83 हजार 160 रूपये की लागत से विकासखण्ड करतला में छात्र-छात्राओं को पौष्टिक नाश्ता प्रदाय, एक करोड़ 21 लाख की लागत से महाविद्यालय उमरेली में विभिन्न निर्माण कार्य,, 32 लाख 60 हजार रूपये की लागत से स्वसहायता समूह हेतु प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण,सात करोड़ 73 लाख 53 हजार 700 रूपये की लागत से गिधौरी चारपारा मार्ग में पुल पुलियासहित निर्माण कार्य, दो करोड़ 37 लाख 14 हजार रूपये की लागत से ओझायाईन से रामपुर पहूँच मार्ग, आठ करोड़ आठ लाख 55 हजार रूपये की लागत से रामपुर से सिरली पहूंच मार्ग निर्माण कार्य,29 करोड़ 80 लाख 75 हजार रूपये की लागत से कोरबा के झगरहा कोरकोमा पसरखेत चचिया मार्ग,एक करोड़ 58 लाख 11 हजार रूपये की लागत से मुडापारा दादर से भालूसटका होते हुएरिसदी बायपास मार्ग निर्माण कार्य, चार करोड़ 38 लाख 83 हजार रूपये की लागत से सीलीभुडु कुदरीचिंगार

रेल के लोकोपायलट से सौर ऊर्जा के रोल मॉडल बने शुकलाल सूर्यवंशी

सूरज बना साथी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से घर हुआ रोशन, जीवन हुआ सरल

कोरबा लोकशक्ति। संवाददाता। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो उसके साथ नई उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। आज वही सूरज देश के हर घर में आत्मनिर्भरता की नई किरण बनकर चमक रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना÷ के रूप में। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्रांति है, जो भारत को ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। इस योजना ने आम नागरिक के जीवन में बदलाव की वह कहानी लिखी है, जिसकी शुरुआत छत से होती है और जिसका उजाला पूरे घर को प्रकाशित कर देता है। अब हर घर की छत बिजली उत्पादन का केंद्र बन रही है, और लोग न केवल अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों में योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ इस उजाले की यात्रा में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यही कारण है कि आज हजारों परिवार बिजली बिल से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रहे हैं। राज्य सरकार ने राज्य में इस योजना को गति देने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई है। पात्र परिवारों को आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूर्ण मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके साथ ही, सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ है। राज्य में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक योजना से वंचित न रहे। डिजिटल पोर्टल, हेल्पडेस्क और जनसहयोग केंद्रों के माध्यम से लोगों को समयबद्ध सहायता प्रदान की जा रही है।

इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों में से एक है कोरबा जिले के खरमोरा निवासी सुकलाल सूर्यवंशी की। जो भारतीय रेल में लोकोपायलट के रूप में कार्यरत सूर्यवंशी ने जब टीवी विज्ञापन के माध्यम से इस योजना के बारे में जाना, तो उन्होंने बिना देर किए इसे अपनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत उन्हें ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त हुई और उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया।

सूर्यवंशी का कहना है कि अब उनका घर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, कूलर सभी उपकरण सौर ऊर्जा से सहज रूप से चल रहे हैं। उन्होंने कहा अब मेरे घर की छत ही मेरी ऊर्जा का स्रोत बन गई है। सूरज की किरणों से मिलने वाली यह स्वच्छ ऊर्जा न केवल बचत का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भरता और गर्व का प्रतीक भी है।

उन्होंने यह भी बताया कि योजना

घर और खेत डूब गए थे..बच्चों की पढ़ाई नहीं डूबेगी

युक्ति युक्तकरण से डुबान क्षेत्र के बच्चों के स्कूल को मिला शिक्षक

कोरबा संवाददाता। चारों तरफ से जंगलों और पर्वतों से घिरा यह गाँव है कोदवारी, जहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार गरीब है। कई दशक पहले जब बांगो बांध बना था तब आसपास रहने वाले परिवारों के खेत पानी में समा गए तो गाँव में रहने वाले अनेक परिवार आसपास जंगलों में जाकर बस गए। गाँव कोदवारी भी ऐसा ही एक गाँव है,जहाँ रहने वाले अधिकांश परिवारों के पास खेत नहीं है। जैसे तैसे वे जीवन यापन करते हैं। इस गाँव में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए शासन ने यहाँ प्राथमिक शाला खोली। कई साल तक विद्यालय में एकमात्र शिक्षक पदस्थ थे, जिससे स्कूल में कक्षा एक से लेकर पाँच तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शिक्षक की कमी के बीच बच्चों के माता-पिता को भी लगता था कि कहीं उनके खेत..उनके घर की तरह बच्चों की पढ़ाई न डूब जाएं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जब सभी जिलों में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी जुटाई गई और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में युक्ति युक्तकरण की गई तो ग्राम कोदवारी के इस विद्यालय को भी नया शिक्षक मिल गया। अब यह विद्यालय एकलशिक्षकीय न होकर द्वि-शिक्षकीय हो गया है और स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चों की कोई भी क्लास खाली नहीं रहती।

कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कोदवारी में वर्ष 1998 से ईजीएस के रूप में शुरू हुई इस विद्यालय को 2005 में प्राथमिक शाला का दर्जा मिला।

बिभास घटक नियुक्त हुए एनटीपीसी कोरबा के परियोजना प्रमुख

कोरबा, एजेंसी। एनटीपीसी लिमिटेड ने बिभास घटक को एनटीपीसी कोरबा के परियोजना प्रमुख (हेड ऑफ प्रोजेक्ट) के रूप में नियुक्त किया है। इससे पूर्व वे एनटीपीसी कोरबा में मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं अनुरक्षण) के पद पर कार्यरत थे। घटक ने 37 वर्षों से अधिक के अपने समृद्ध करियर में विद्युत संयंत्र संचालन और अनुरक्षण के क्षेत्र में गहरा अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने एनटीपीसी की कई प्रमुख परियोजनाओं में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई और अपने अनुभव एवं प्रबंधन कौशल के माध्यम से संगठन की परिचालन दक्षता और प्रदर्शन मानकों को सशक्त बनाया है। कोरबा में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, घटक ने एनटीपीसी झाबुआ और एन एस पी सी एल-भिलाई में ओ एंड एम प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहाँ उनके नेतृत्व में संयंत्र की परिचालन उत्कृष्टता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक, घटक ने 1988 में एनटीपीसी में एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की। उन्होंने सिंगरौली, झज्जर, कहलगांव, विंध्याचल, पीएमआई नोएडा, झाबुआ और भिलाई जैसी प्रमुख इकाइयों में कार्य करते हुए एनटीपीसी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत दैनिक स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन

750 सामान्य व 51 मेगा स्पेशिलिस्ट शिविरों में 45359 लोगों को पहुंचाया गया स्वास्थ्य लाभ

कोरबा संवाददाता। जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण देखभाल, टीकाकरण और पोषण के प्रति जागरूकता कोबढ़ावा देने, महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तकजिला चिकित्सालय, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रों में दैनिक स्वास्थ शिविर आयोजन किया गया।शिविरों में रोगों की पहचान, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित कर गैर संचारी रोगों, कैंसर एनिमिया, टीबी, सिकल सेल रोग, मातृ एंव शिशु की जाँच एवं उपचार किया गया है।साथ ही महिलाओं को स्वस्थ जीवनशैली, जागरूकता के लिए परामर्श सत्र के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं में एनिमिया,पोषण की कमी, महावारी से जुड़ी समस्याओं और सिकल सेल जैसी बिमारियों समय पर जाँच नहीं होने कीवजह से गंभीर रूप ले लेती हैं। इन समस्याओं को दूर करने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत स्वास्थ्यकेन्द्रों में शिविरों का आयोजन कर महिलाओं में बिमारियों की स्क्रीनिंग कर उपचार प्रदान किया गया है।अभियान में प्रतिदिनविभिन्न थीम के अनुरूप षिविर आयोजित हुए जिसमें नारी आरोग्य उत्सव,स्वस्थ किशोरी सशक्त भविष्य, वीमेन वेलनेसवाक डे, मेरा स्वास्थ मेरी शक्ति,पीएम जनमन स्वस्थ पर्व, स्वास्थ्य सम्मेलन दिवस, छत्तीसगढ़िक महतारीहम सब कि जिम्मेदारी, नारी/अन्नपूर्णा पोषण दिवस,स्वास्थ्य पर्व, स्वस्थ माँ दिवस, स्वास्थ्य संजीवनीकैंप, उत्सव भी स्वास्थ्य भी,दशहरा डे, फैसलिटेसन डे इत्यादी षामिल है।

जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगाये गए 750 सामान्य एवं 51 मेगा स्पेशिलिस्टशिविरों में कुल 45359 लोगों का जाँच किया गया जिसमें 5200 गर्भवती महिलाओं की जाँच, 18192 एनिमियाजॉच,9921 सिकलसेल जाँच तथा 54 सिकल सेल कार्ड वितरण 1968 टीबी जाँच, 28483 बीपी जाँच,27630शुगर जाँच तथा 2091 कैंसर जाँच(ओरल, ब्रेस्ट,सर्वाइकल) किया गया। साथ ही 225 वयवंदन कार्ड बने,10 लोगों ने रक्तदान किये124 लोग निक्षयमित्र बनने पंजीकृत हुए तथा 1313 बच्चों को टीकाकृत कियागया।

उरगा-कुसमुंडा नई लाइन का खाली मालगाड़ी चलाकर किया गया परीक्षण

जल्द शुरू किया जाएगा कोल प्रेषण

कोरबा, लोकशक्ति

जिले में उरगा से कुसमुंडा तक बनाई गई 12.637 किलोमीटर लंबी नई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेल लाइन पर पहली बार 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से मालगाड़ी चलाकर रेल अधिकारियों ने इस लाइन का परीक्षण किया। इसके साथ ही कोल प्रेषण के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में उरगा से कुसमुंडा तक 12.637 किलोमीटर लंबी नई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेल लाइन रेल खंड छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर (गेवरा रोड-पेंड्रा रोड) नई रेल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बतौर परीक्षण के लिए चलाई गई इस मालगाड़ी की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई थी। इस रेल लाइन पर अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर तय की गई है, लेकिन इस गति से चलाने के लिए अनुमति अभी नहीं मिली है। फिलहाल इस मार्ग पर जो भी मालगाड़ी चलाई जाएगी उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

इरकॉन कंपनी ने किया इसका निर्माण कार्य उरगा-कुसमुंडा बाइपास नई रेल लाइन का कार्य इरकॉन कंपनी ने किया है। 12.637 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में 10.998 किलोमीटर का कार्य इरकॉन ने किया। वहीं शेष वर्किंग रेलवे के गतिशक्ति विभाग ने किया है। सिंगल रेल लाइन पर हसदेव नदी पर एक किलोमीटर लंबे रेल ब्रिज के साथ 2 लेवल क्रासिंग, 3 आरओबी के साथ 2 एचटी इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रासिंग है। सिंगल बाइपास रेल लाइन पर दोनों तरफ से मलगाड़ी चलाई जाएगी।

निरीक्षण पश्चात अधिकारियों ने दी थी हरी झंडी नई रेल लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम में सीपीएम एसईसीआर, एडीआरएम बिलासपुर, डिप्टी सीई बिलासपुर मंडल और इरकॉन समेत बिलासपुर डिवीजन के संबंधित शाखाओं के अधिकारी शामिल थे। संबंधित पीएचओडी ने संयुक्त सुरक्षा ने प्रमाणित किया है कि सीटीई द्वारा अनुशंसित अधिकतम 30 किमी प्रति घंटे की गति से माल यातायात चलाना सुरक्षित है।

शहर की क्रॉसिंग पर दबाव हो जाएगा कम

कुसमुंडा खदान का कोयला साइडिंग से सीधे बाइपास होकर उरगा पहुंचेगा। वहीं उरगा से खाली रैक कुसमुंडा खदान पहुंचेगा। सामान्य मौसम में कुसमुंडा से रोजाना 10 से 12 रैक कोयला प्रेषित होता है। वहीं इतनी ही खाली मालगाड़ी साइडिंग पहुंचती हैं। परीक्षण होने के बाद अब जल्द ही इस ट्रैक पर मालगाड़ी नियमित चलने लगेगी। ऐसा होने के साथ ही कोरबा शहर के बीच से गुजरी रेल लाइन पर मालगाड़ी का दबाव कम होने के साथ ही क्रासिंग पर लोगों को खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जलभराव और मलबा भर जाने से कोयला उत्पादन पूरी तरह ठप्प

सुरक्षा को लेकर कर्मचारी संगठनों ने एसईसीएल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

कोरबा, । लगातार हो रही भारी बारिश ने कोरबा जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ी है एसईसीएल की एशिया की सबसे बड़ी गेवरा कोयला खदान पर। खदान परिसर में भारी जलभराव और मलबा भर जाने से कोयला उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। करोड़ों की मशीनें, डंपर और मोटर पंप पानी और कीचड़ में दब गए हैं-जिससे न सिर्फ उत्पादन पर असर पड़ा है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, खदान में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। हर साल की तरह इस बार भी बारिश से पहले ड्रेनेज और सुरक्षा इंतजाम अधूरे छोड़े गए। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी सी लगातार बारिश ने खदान को तालाब में तब्दील कर दिया। मजदूरों और कर्मचारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में पानी इतना भर गया कि भारी मशीनें तक बंद करनी पड़ीं। वहीं, खदान में काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि बारिश के दौरान सुरक्षा के कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए - जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा बना हुआ है। खदानों में कोयला उत्खनन और परिवहन दोनों ही प्रभावित हो चुके हैं। इससे एसईसीएल को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय नागरिकों और कर्मचारी संगठनों ने एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि हर साल यही कहानी दोहराई जाती है, लेकिन प्रबंधन सीखने को तैयार नहीं।

इसरो SAC अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉ एन.एम. देसाई ने किया विद्यार्थियों से संवाद, कहा प्रोजेक्ट अंतरिक्ष सराहनीय कार्य, इससे प्रदेश के बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बढ़ेगी रुचि।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने छीनी दो जानें, मां और दो वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत

दुर्ग, (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार को एक हृदयविदारक सड़क हादसे में मां और उसकी दो साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुखद घटना गया नगर क्षेत्र में हुई, जब एक मुरम से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूटी से गिरीं महिला और मासूम बच्ची को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार, गया नगर निवासी विकास साहू अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्कूटी से किसी काम के लिए निकले थे। जैसे ही वे दयानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास पहुंचे, सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली को देख स्कूटी चालक विकास ने ब्रेक लगाया। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से पीछे बैठी पत्नी और बच्ची स्कूटी से गिर गईं। पीछे से तेज गति में आ रही ट्राली ने दोनों को कुचल दिया। घटना होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पिता विकास साहू गहरे सदमे में हैं।

स्थानीय निवासी दिनेश देवांगन ने बताया कि यह सड़क अत्यधिक व्यस्त रहती है और क्षेत्र में कई स्कूल होने के कारण बच्चों की आवाजाही दिनभर बनी रहती है। इसके बावजूद सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से हादसों का खतरा लगातार बना रहता है।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बलरामपुर/रामानुजगंज में दिल दहला देने वाली घटनाः 10 वर्षीय छात्र ने लगाई फांसी

बलरामपुर, (आरएनएस)। रामानुजगंज नगर में एक 10 वर्षीय बालक की आत्महत्या की दुखद खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले हार्दिक रवि (पुत्रः भारत जसवंत रवि) ने सोमवार शाम को अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस इस हृदयविदारक घटना के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम लगभग 6:30 बजे हार्दिक अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। अचानक वह घर के एक कमरे में चला गया। कुछ समय बाद जब उसका भाई उसे बुलाने के लिए कमरे में गया, तो उसने हार्दिक को फंदे से लटका हुआ पाया। यह भयावह दृश्य देखकर वह तुरंत चिल्लाता हुआ बाहर आया और परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किया।

घटना के समय हार्दिक के माता-पिता, भारत जसवंत रवि और उनकी पत्नी, किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। खबर मिलते ही पिता तुरंत घर पहुंचे और आनन-फानन में बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्दिक को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना ने पूरे नगर को स्तब्ध कर दिया है।

हाथी के कुचलने से महिला एवं बच्चे की मौत

एमसीबी, भरतपुर वनांचल क्षेत्र के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पार्क परिक्षेत्र में हाथी ने महिला को कुचल दिया. घटना मंगलवार रात की है. महिला और उसके बच्चे घर में सो रहे थे उस वक्त नर हाथी ने हमला किया. हाथी ने जैसे ही कच्चे मकान को धक्का देना शुरु किया घर के भीतर बच्चों के साथ सो रही इतवरिया बालंद जाग गई. घर के बाहर हाथी की मौजूदगी से पूरा परिवार दहशत में आ गया. इतवरिया अपने बच्चों के साथ भागने की तैयारी कर रही थी तभी हाथी ने उनको कुचल दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. 1 बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. जख्मी बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है.

हाथी के हमले में महिला की मौतः ग्रामीणों के अनुसार, यह वही जंगली नर हाथी है जो पिछले कई महीनों से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच लगातार विचरण कर रहा है. हाथी अब तक कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है और कई ग्रामीणों की जान भी ले चुका है. इसके बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है.

गांव की ओर हाथी के आने की कोई सूचना वन विभाग से नहीं मिली थी. यदि सूचना मिल जाती तो वे सुरक्षित स्थान पर शरण ले सकते थे और यह दुखद घटना टल सकती थी. हमारी मांग है कि इस जंगली हाथी को पकड़कर जंगल सफारी या चिड़ियाघर में भेजा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होंः स्थानीय निवासी, ढाब गांव

जशपुर वनमण्डल में मनाया जा रहा वन्यजीव संरक्षण सप्ताह

75 स्कूलों में 8 हजार से अधिक विघार्थियों को हाथी के व्यवहार और गतिविधियों की दी गई जानकारी जशपुर ,। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर से अक्टूबर 2025 तक वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन जशपुर वनमण्डल के समस्त परिक्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में इस वर्ष 2025 में वन्यजीव सप्ताह मनाये जाने हेतु ''मानव-पशु सह अस्तित्व'' विषय चुना गया है।

नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130-डी

कुतुल से नीलांगुर महाराष्ट्र बॉर्डर तक एनएच-130-डी का होगा निर्माण

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत ङ्क मुख्यमंत्री श्री साय

कुतुल से नीलांगुर महाराष्ट्र बॉर्डर तक एनएच-130-डी का होगा निर्माण

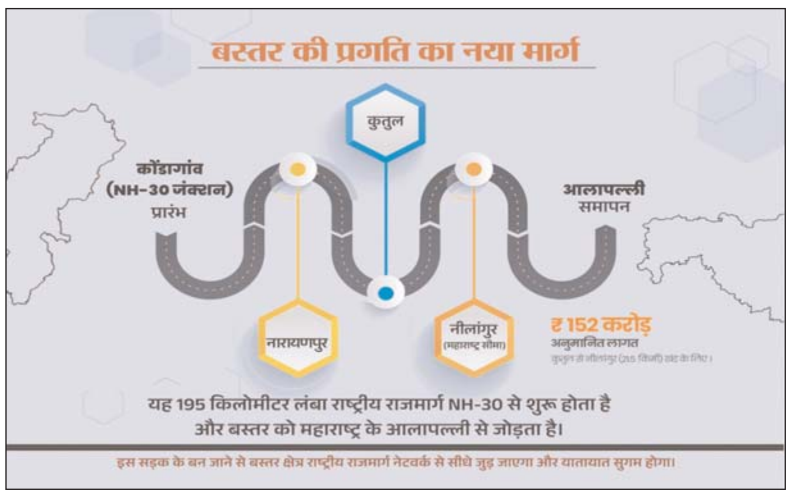

रायपुर, बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी। नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है।

बस्तर में माओवादियों को एक और झटका, 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

जगदलपुर, संवाददाता

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। लंबे समय से सक्रिय और वांछित माओवादी नेता मंदा रूबेन उर्फ कन्नन्ना उर्फ मंगन्ना (67 वर्ष) ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया है। रूबेन पर सरकार ने 8 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

मंगलवार को उसने तेलंगाना के वारंगल में पुलिस आयुक्त सनप्रीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और संगठन से मोहभंग जैसे कारणों ने उसे सरेंडर के लिए मजबूर किया। मंदा रूबेन दक्षिण बस्तर के एक वरिष्ठ डिविजनल कमेटी सचिव के रूप में सक्रिय था और साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का महत्वपूर्ण सदस्य भी रह चुका है। उसके आत्मसमर्पण को सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरेंडर के बाद स्थानीय पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि का चेक सौंपा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के आत्मसमर्पण माओवादी संगठनों की गिरती पकड़ और कमजोर होती रणनीति की ओर संकेत करते हैं।

विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
प्रदेश के राजस्व वृद्धि के लिए सभी अधिकारी लें जिम्मेदारी मंत्री श्री चौधरी

रायपुर,

राज्य कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक आज नवा रायपुर में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल, आयुक्त राज्य कर श्री पुष्पेन्द्र मीणा सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, राजस्व संग्रह, कर चोरी की रोकथाम और प्रशासनिक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2022 तक राज्य को 14 प्रतिशत संरक्षित राजस्व में कमी की स्थिति में केंद्र से मुआवजा प्राप्त होता था। वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब सभी अधिकारियों को अपने कार्य प्रदर्शन के माध्यम से राजस्व वृद्धि की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों में की गई कमी का लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए। साथ ही, राज्य के बाहर से बेस ऑयल मंगाकर बिना कर अदा किए बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि कर चोरी रोकने के लिए संगठित और ठोस प्रयास आवश्यक हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को कार्य में पूर्ण पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने, अनुशासन बनाए रखने तथा कार्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया जाए। मंत्री श्री चौधरी ने अन्य राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में लागू सफल कर प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ में लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में नए नियुक्त अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा फर्जी या गैर-पंजीकृत फर्मों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों में दक्षता, विशेषज्ञता और पारदर्शिता लाएँ तथा दैनिक कार्यों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखें। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों से राज्य के राजस्व हित में निष्ठा, समर्पण और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

10 अक्टूबर को साय कैबिनेट की बैठक

धान खरीदी की तारीख समेत कई मुद्दों पर हो सकता है फैसला

रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर, नवा रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक आयोजित होगी। साय कैबिनेट की इस बैठक में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एनएचएम कर्मचारियों और राज्योत्सव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले पिछली बैठक 30 सितंबर को हुई थी। पिछली कैबिनेट बैठक में 100 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण राशि 24,50,05,457 (चौबीस करोड़ पचास लाख पांच हजार चार सौ सत्तावन रुपये) एकमुश्त वापस करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रिपरिषद ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया था।

संगठन सृजन से कार्यकर्ताओं में बढ़ा उत्साह- दीपक बैज :

जनहित के मुद्दों को पीसीसी चीफ ने पत्रकारवार्ता में दी अहमियत

रायपुर, (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती और विस्तार के लिए 'संगठन सृजन' कार्यक्रम चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का आगमन हो चुका है और कुछ जिलों में शीघ्र ही उनके पहुंचने की संभावना है।

दीपक बैज ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम से पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता न सिर्फसक्रिय रूप से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं बल्कि अपनी राय भी खुलकर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का प्रतीक है, जो अन्य राजनीतिक दलों से इसे अलग करती है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चिंता

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर करते हुए बैज ने कहा कि हाल

के दिनों में विभिन्न सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अमानक दवाओं के मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। खासतौर पर बच्चों से जुड़ी दवाओं, जैसे कि कफसिरप, को लेकर देश भर में जो सतर्कता दिखाई गई है, उसी अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच और निगरानी की जानी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर बना रहे।

राशन कार्ड से जुड़े मसले पर उठाए सवाल

दीपक बैज ने प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डों के पुनः सत्यापन (KYC) प्रक्रिया के बाद संभावित निरस्तीकरण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि 32 लाख उपभोक्ताओं को आगामी नवंबर माह से राशन प्राप्त नहीं होगा, तो यह एक गंभीर विषय है।

उनका कहना था कि पूर्व में भी राशन कार्ड आधार से लिंक कर बनाए गए थे, ऐसे में अचानक इस प्रकार की प्रक्रिया से आम जनता को असुविधा हो सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के राशन प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

शैक्षणिक संस्थानों में मरम्मत कार्यों पर पारदर्शिता की अपेक्षा*

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दुर्ग जिले के कोंदुल ब्लॉक में स्कूलों के मरम्मत कार्य को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वहां के 163 स्कूलों के लिए स्वीकृत 6.63 करोड़ रुपये की राशि के बावजूद मरम्मत कार्य अधूरे हैं, जबकि भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। बैज ने इस संदर्भ में पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा इस विषय पर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि जनमानस इस विषय को लेकर गंभीर है, और प्रशासन को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

धान खरीदी के संबंध में कांग्रेस की मांगें

किसानों के पंजीयन को लेकर भी बैज ने चिंता जताई और कहा कि इस बार अब तक केवल 21 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जबकि पिछले साल 27 लाख किसानों ने धान बेचा था। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों का पंजीयन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है, उन्हें सहूलियत दी जाए और अक्टूबर माह भर पंजीयन की प्रक्रिया जारी रखी जाए।

सरकार द्वारा 17 नवंबर तक विभिन्न दस्तावेज के साथ आवेदन मंगाये

रायपुर, संवाददाता।

प्रदेश में गोल्ड, चूना खदान और लौह अयस्क के खदानों की नीलामी करने के लिए राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खुला टेंडर आमंत्रित किया गया है। इधर राजधानी के खरोरा के पास एक विख्यात सीमेंट कंपनी द्वारा चूना खदान लेने के लिए दिये गये आवेदन पर छग पर्यावरण मंडल ने जनसुनवाई करने का निश्चय किया गया है। इस चूना खदान को लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी रोष है। छग के खनिज एवं भूगर्भ संचालनालय द्वारा विभिन्न जिलों में स्थित चूना लौह अयस्क सोना तथा अन्य खदानों की नीलामी के लिए खुला टैंडर आमंत्रित किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा निविदा के लिए खनन का स्तर भी तय कर दिया गया है तथा वर्तमान में इसके एकड़ की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। संचालक खनिज एवं भौमिकी विभाग द्वारा इस संबंध में बोली लगाने वालों से निर्धारित दर पर बोली लगाने के लिए आवेदन मंगाये गये हैं। इसे विभाग के वेबसाइट में जमा किया जा सकता है। संचालक ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में जीएसटी के संबंध में बोलीदारों की स्थिति स्पष्ट करना होगा। सरकार द्वारा 17 नवंबर तक विभिन्न दस्तावेज के साथ आवेदन मंगाये गये है। 19 नवंबर तक इस पर फैसला हो जाएगा। **महासमुंद में मिला स्वर्ण भंडार -** महासमुंद के आसपास स्पर्ण आधारित एक खदान की भी नीलामी की जाएगी। यह कुल 150 हेक्टेयर में उपस्थित है। इसका खनन क्षेत्र जी 3 है। इसके अलावा कबीरधाम में एक ब्लाक, खैरागढ़ छुईखदान जिले में चूना खदान खैरागढ़ छुईखदान के गोपालटोला में लौह अयस्क खदान तथा बलरामपुर में बेस मेटल से संबंधित खदान की नीलामी के लिए ओपन टेंडर आमंत्रित किया गया है। **रायपुर जिले में प्रख्यात सीमेंट कंपनी को चूना खदान देने जनसुनवाई**

पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा खरोरा रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले एक गांव में दस एकड़ चूना पत्थर खदान की नीलामी के पूर्व जनसुनवाई होगी। यह कंपनी एक विख्यात औद्योगिक समूह की बताई जाती है जोकि भारत तथा अंतरराष्ट्रीय लेबल की है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)